● वर्ष-3
● अंक-308
रायपुर, बुधवार
07 अगस्त 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› मानसून के मौसम में घर के अंदर...

मानसून संसद सत्रः नड्डा और डेरेक के बीच नोकझोंक

कोई भी राज्य प. बंगाल का मॉडल नहीं अपनाना चाहेगा :अमित शाह

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र जारी है। नई सरकार गठन के बाद इस सत्र में बजट भी पेश किया गया। बजट को लेकर लगातार चर्चा जारी है। इन सब के बीच आज संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को लेकर अपना वक्तव्य दिया। आज संसद में जेपी नड्डा और टीएमसी सदस्य के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा में भाजपा ने साफ तौर पर दावा किया कि देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। आज लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना वक्तव्य दिया। लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने और भारतीय चिकित्सा सेवा शुरू करने की भी मांग उठी है। चलिए आपको बताते हैं कि आज दोनों सदनों में क्या कुछ हुआ है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत रॉय के प्रश्न के उत्तर में कटाक्ष करते हुए कहा कि देश का कोई भी राज्य अपने यहां पश्चिम बंगाल का मॉडल नहीं अपनाना चाहेगा। रॉय ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान वामपंथी उग्रवाद से जुड़ा पूरक प्रश्न पूछा था। उन्होंने पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद के खात्मे का हवाला देते हुए सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार इस मॉडल को दूसरे राज्यों में लागू करेगी?

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 32,440 करोड़ रुपये के प्रीमियम के मुकाबले किसानों को 1.64 लाख करोड़ रुपये के बीमा दावे का भुगतान किया गया है। प्रश्नकाल के दौरान योजना पर एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछली योजना की विसंगतियों को दूर करके इसे किसान हितैषी बनाया है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब मंत्री का उत्तर उन्हें समझ नहीं आया तो भला किसानों को क्या समझ आएगा। इस पर चौहान ने कहा कि आश्चर्य है कि सदस्य को उत्तर नहीं समझ नहीं आया। कृषि मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा, ''किसान समझदार हैं।''

संसद के मकर द्वार के पास मंगलवार को विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' ('इंडिया') के सदस्यों के प्रदर्शन के कुछ देर बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी दलों से चर्चा के बाद सहमति बनी थी कि संसद भवन के किसी भी द्वार पर धरना और प्रदर्शन नहीं किया जाएगा और सभी को इस पर अमल करना चाहिए।

कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के माध्यम से आम लोगों तथा मध्य वर्ग को नुकसान पहुंचाया है तथा अमीरों को फायदा पहुंचाया है। सदन में 'वित्त (संख्याक 2) विधेयक, 2024' पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद डॉक्टर अमर सिंह ने कहा कि यह सरकार आम आदमी और वेतनभोगी वर्ग से कर के रूप में एक-एक रुपये वसूल लेना चाहती है, जबकि कॉरपोरेट लोगों को छूट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं देश के खिलाफ माहौल बनाने के प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि इस कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। दुबे ने लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कांग्रेस के समय धनशोधन विरोधी कानून (पीएमएलए) तथा आयकर से जुड़े कानूनों को सख्त किया गया था, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में ईमानदारी से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की राज्यसभा सदस्य फौजिया खान ने बच्चों में ऑनलाइन वीडियो गेम के बढ़ते चलन और उसकी सामग्री से उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को लेकर मंगलवार को चिंता जताई.

परिवार किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला : साय

मेगा पालक शिक्षक बैठक कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने पालकों से जाने पालक शिक्षक संवाद के अनुभव

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बंदरचुंआ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित मेगा पालक शिक्षक बैठक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने पालक शिक्षक बैठक में शामिल होकर पालकों से कार्यक्रम को लेकर उनके अनुभव जाने। बच्चों के माता पिता के साथ कुछ बच्चों के दादा दादी भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि परिवार किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला है और माता पिता पहले गुरु। शासकीय स्कूलों में पालक शिक्षक संवाद का कार्यक्रम शुरू किया गया है जिससे पालकों को उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी मिले और बच्चे के शैक्षणिक प्रगति में उनकी भी सहभागिता हो। उन्होंने बताया कि आज स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने पालकों से अनुरोध किया कि अपने बच्चों के शिक्षकों से सतत संपर्क में रहें। इससे बच्चे के पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी मिलेगी ही साथ ही आपकी सहभागिता से बच्चे के गलत संगत में जाने की आशंका भी नही होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पालकों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी साढ़े पांच हजार संकुलों में मेगा पालक शिक्षक मीटिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री महोदय ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह बात रखी कि प्राइवेट स्कूल में पीटीएम आयोजित होता है लेकिन सरकारी स्कूलों में यह नही होता है। इसे हमें लागू किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह पालक शिक्षक बैठक आयोजित किया जा रहा है। यह बच्चे के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाएगा। पालक शिक्षक बैठक का मुख्य उद्देश्य है पढ़ाई लिखाई और स्कूली गतिविधियों में शिक्षकों के साथ पालकों की सहभागिता हो।

बांग्लादेश में राष्ट्रपति ने किया संसद भंग

खालिदा जिया रिहा, अमेरिका ने रद किया शेख का वीजा

ढाका। शेख हसीना के बांग्लादेश के प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के एक दिन बाद, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अंतरिम प्रशासन के गठन का रास्ता बनाने के लिए देश की संसद को भंग करने की घोषणा की। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन की तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और भेदभाव के खिलाफ छात्र आंदोलन के नेताओं के साथ एक बैठक के निर्णय के आधार पर, राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया गया। इसमें आगे कहा गया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया है। अमेरिका ने शेख हसीना का अमेरिकी वीजा रद कर दिया है। उसने कहा है कि शेख हसीना का अमेरिका में स्वागत नहीं है। शेख हसीना और अमेरिका के बीच रिश्ते बहुत तनावपूर्ण थे।

बयान में कहा गया है कि 1 जुलाई से 5 अगस्त तक छात्र आंदोलन और विभिन्न मामलों में हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिनमें से कई को पहले ही रिहा किया जा चुका है। इससे पहले दिन में बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधान मंत्री खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया था। राष्ट्रपति की प्रेस टीम ने कहा कि शहाबुद्दीन के नेतृत्व में एक बैठक में बेगम खालिदा जिया को तुरंत रिहा करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति के बयान में कहा गया, बैठक में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा करने का भी फैसला किया गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री 78 वर्षीय जिया खराब स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती हैं।

दस सालों में पांच राज्यों में पड़ी सबसे भीषण गर्मी

नई दिल्ली। इन दिनों हो रही लगातार बारिश ने भले ही फिलहाल भीषण गर्मी पर अंकुश लगाया हो, लेकिन अभी भी उमस बरकरार है। इस बीच, एक नए शोध में बताया गया है कि 2013-22 के दशक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई। स्वतंत्र विकासात्मक संगठन आईपीई ग्लोबल लिमिटेड और ईएसआरआई इंडिया टेक्नोलॉजीज की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। गर्म जलवायु में मानसून का प्रबंधन शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दशक में तटीय क्षेत्रों के 74 प्रतिशत जिले, मैदानी इलाकों के 71 प्रतिशत और पहाड़ी इलाकों के 65 प्रतिशत जिलों में अत्यधिक गर्मी का असर उच्च से बहुत अधिक तक दर्ज किया गया। वहीं, इस दौरान मैदानी और पहाड़ी जिलों में लू के दिनों में 36 प्रतिशत की बढोतरी भी देखी गई वहीं, तटीय जिलों में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा इस दशक में शीर्ष पांच हीटवेव हॉटस्पॉट राज्य थे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज्यादा भीषण गर्मी इस दशक में 2015 में हुई, जो 1998 की घटना के बाद दूसरी सबसे घातक घटना थी। वहीं, इस दशक में पिछले दो दशकों की तुलना में कम संचयी हीटवेव वाले दिन दर्ज किए गए।

इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मार्च-अप्रैल-मई की अवधि और उसके बाद जून-जुलाई-अगस्त-सितंबर की अवधि के दौरान मैदानी इलाकों के जिलों में सबसे अधिक गर्मी वाले दिन देखे गए। वहीं, पिछले दशक में तटीय जिलों में आवृत्ति और तीव्रता दोनों में हीटवेव की संख्या में गिरावट देखी गई। ऐसा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती गतिविधियों में हुई बढोतरी के कारण संभव हुआ। इस रिपोर्ट में इन 10 सालों में भीषण गर्मी और सनस्ट्रोक से होने वाली मौतों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक,2013 से 10 वर्षों में भारत में अत्यधिक गर्मी और सनस्ट्रोक ने 10,635 लोगों की जान ले ली। इस अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 2203 मौतें दर्ज की गईं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में1,485, तेलंगाना में 1,172, पंजाब में 1,030, बिहार में 938, महाराष्ट्र में 867, ओडिशा में 609, झारखंड में 517, हरियाणा में 461, पश्चिम बंगाल में 357, राजस्थान में 345, गुजरात में 263, और मध्य प्रदेश में 213 लोगों की मौत हुई। वहीं, दिल्ली में 13 मौतें दर्ज की गईं।

प्रमुख समाचार

प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर मद से खर्च हुए 6 करोड़

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनियां सीएसआर निधि से राशि खर्च कर रही हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से सवाल किया था कि, कंपनियों ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व में खेल कार्यकलापों पर होने वाले व्यय को शामिल किया है और छत्तीसगढ़ में सीएसआर निधि से खेल कार्यकलापों पर होने वाले खर्च की जानकारी मांगी थी। जिसपर कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा बताया कि, पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2020-21 से 2022-23 के दौरान देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सभी कंपनियों द्वारा सीएसआर निधि से राशि खर्च की गई है। जिसमें ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शामिल है। छत्तीसगढ़ में कंपनियों द्वारा खेलों पर 2022-23 में 5.72 करोड़ रुपए राशि खर्च की गई है।

छग सहित पूरे देश में सडक़ों पर घुमंतू पशुओं का मुद्दा संसद में उठा

नई दिल्ली/कोरबा। लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने सदन में पशुधन विकास पर अपनी बात प्रमुखता से रखी। उन्होंने अपने उद्बोधन की शुरूआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उन पंक्तियों से की जिसमें कहा गया कि - किसी राष्ट्र की महानता व उसकी नैतिक उन्नति का अंदाजा हम वहाँ के पशुओं के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते है। सांसद ने कहा कि भारत की 80 प्रतिशत आबादी पशु पालन के व्यवसाय पर निर्भर है किंतु इन पशुओं के संरक्षण और टीकाकरण के लिए जिस गति से कार्य होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। विभिन्न राज्यों में रोगों से बचाव के लिए पहले दौर में कोई टीकाकरण नहीं हुए। भारत में वर्ष 2021-22 में त्वचा रोग का प्रकोप से कई मवेशी मारे गए। विभाग द्वारा मवेशियों का शारीरिक टीकाकरण लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करनी चाहिए और टीकाकरण के लिए पर्याप्त जनशक्ति की भर्ती व प्रशिक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए।

आरक्षण संबंधी फैसलाः सीजेआई को धमकी देने वाला गिरफ्तार

बैतूल। भीम सेना की मध्य प्रदेश इकाई के प्रभारी पंकज अतुलकर को आरक्षण संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मंगलवार को बैतूल से गिरफ्तार किया गया। गंज थाना प्रभारी रविकांत दहेरिया ने बताया कि अतुलकर (34) को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अतुलकर ने सोशल मीडिया मंच 'फेसबुक' पर पोस्ट कर कहा था कि वह ''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को गुलाम बनाने का फैसला'' देने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को जान से मार देगा। इसके बाद सोमवार को उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके।

दिल्ली दौरा उद्धव के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण

मुंबई। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने मंगलवार को तीन दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे शिवसेना-उद्धव बाला साहेब ठाकरे (शिवसेना-यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा कि ठाकरे मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के लिए महाराष्ट्र के बारिश प्रभावित लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। निरुपम ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक, पुणे और राज्य के अन्य हिस्सों में भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी की अपनी यात्रा रद्द कर दी। निरुपम ने दावा किया, आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बेहतर सौदा करने के लिए ठाकरे दिल्ली गए हैं। ऐसा लगता है कि वे बारिश से प्रभावित लोगों की परेशानियों को दूर करने के बजाय अपने राजनीतिक हितों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना-यूबीटी प्रमुख आगामी विधानसभा चुनावों के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए वह कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं। ठाकरे दिन में पहले ही दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वह कांग्रेस के कई नेताओं और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के घटक दलों से मिल सकते हैं।

नदियों में प्लास्टिक कचरे सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जल निकायों में प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों की अनियंत्रित डंपिंग पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, चेतावनी दी है कि यह प्रदूषण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय गिरावट का कारण बन रहा है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों के एकीकृत प्रयास और जनता के सहयोग के बिना, अवैध निर्माणों को संबोधित करने और गंगा सहित नदियों में पानी की गुणवत्ता में सुधार करने का कोई भी प्रयास भ्रम बना रहेगा। पीठ ने अपने 2 अगस्त के आदेश में कहा कि प्लास्टिक के डंपिंग से गंभीर पर्यावरणीय क्षति हो रही है और देश में नदी तटों और जल निकायों में जलीय जीवन पर भी असर पड़ रहा है। जब तक जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा लोगों के सहयोग से ठोस प्रयास नहीं किया जाता, अवैध/अनधिकृत निर्माणों को निशाना बनाने के प्रयासों के बावजूद, देश में गंगा नदी/अन्य सभी नदियों और जल निकायों में पानी की गुणवत्ता में वांछित सुधार भ्रम ही रहेगा। अदालत ने भारत सरकार और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को आदेश में उल्लिखित पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करते

बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता और भावी सरकार को लेकर अनिश्चितता भी बढ़ी

डॉ. धनंजय

बांग्लादेश में कई सप्ताह से चल रहे छात्रों एवं युवाओं के व्यापक आंदोलन के चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ने के साथ-साथ देश भी छोड़ना पड़ा है। बांग्लादेश सेना के प्रमुख जेनरल वकार ने साझा सरकार गठित करने की बात कही है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को यह आश्वासन भी दिया है कि सभी मौतों की जांच की जायेगी और उनकी मांगों पर विचार किया जायेगा। जुलाई से जारी प्रदर्शनों में 300 से अधिक लोगों की मौत और बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाओं से यही इंगित होता है कि वहां स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है।

प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के साथ प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग तो पूरी हो गयी है, पर इसी के साथ राजनीतिक स्थिरता और भावी सरकार को लेकर अनिश्चितता भी बढ़ गयी है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि साझा सरकार में अवामी लीग की क्या भूमिका होगी। अगर उसे सरकार में शामिल नहीं किया जाता है, तो क्या स्थिरता बहाल हो पायेगी, और यदि उसे नये शासन का हिस्सा बनाया जाता है, तो क्या यह प्रदर्शनकारियों को स्वीकार्य होगा- ऐसे सवाल बांग्लादेश के सामने हैं। यह भी अहम सवाल है कि क्या देश में नये चुनाव होंगे।

मौजूदा आंदोलन की वजह यह है कि उच्च न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय का एक अंग) ने सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण को बहाल कर दिया था, जिसे 2018 में हटा दिया गया था। इस फैसले के बाद कुल आरक्षण 56 प्रतिशत हो गया था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय से सरकारी नौकरियों में हर तरह के आरक्षण में भारी कटौती करते हुए 93 प्रतिशत सीटों को आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया था।

इस पर सरकार की अपील पर सात अगस्त को निर्णय आना है। पर अब ऐसा लगता है कि यह मामला कुछ समय के लिए टाल दिया जायेगा। प्रदर्शनकारी इस बात से बहुत क्षुब्ध हैं कि उनकी मांगों पर विचार करने और उनसे संवाद स्थापित करने की जगह प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी की ओर उन्हें रजाकारों का वंशज तथा आतंकवादी कहा गया है। रजाकार वहां एक अपमानजनक संबोधन है क्योंकि यह संज्ञा उन लोगों से जुड़ी हुई है, जो बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में पाकिस्तान सेना का साथ देते थे और स्वतंत्रता सेनानियों को निशाना बनाते थे।

हालांकि यह आंदोलन आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ था और मुख्य रूप से इसमें छात्र और युवा शामिल थे, पर बाद में इसमें शेख हसीना के विरोधी दल तथा सरकार की नीतियों एवं कार्यशैली से क्षुब्ध लोग भी शामिल होते गये। अन्य मसलों के अलावा भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा भी आंदोलन की मांगों का हिस्सा बन गया। पुलिस के दमन तथा शेख हसीना के समर्थकों के हिंसक हमलों ने लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ा दिया।

बहुत से अन्य देशों की तरह बांग्लादेश में भी युवाओं की पहली कोशिश सरकारी नौकरी हासिल करने की होती है। इस कारण आरक्षण एक त्वरित कारण बन गया। वहां बड़ी संख्या में सरकारी पद खाली भी हैं। यदि लोगों को नौकरियां मिलती रहतीं, तो यह स्थिति संभवतः पैदा ही नहीं होती। हालांकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, पर हालिया वर्षों में विभिन्न कारणों, विशेषकर कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध आदि, से आर्थिक विकास की गति पर नकारात्मक असर पड़ा है। महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं वहां भी हैं।

शेख हसीना 2009 से प्रधानमंत्री रही थीं और लगातार चुनाव जीत रही थीं। उन चुनाव के साफ-सुथरे नहीं होने को लेकर अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी सवाल उठाये जाते रहे हैं। पिछले चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार भी किया था क्योंकि उसके नेताओं को लगातार हिरासत में रखा गया है।

इन प्रदर्शनों से यह भी साबित होता है कि शेख हसीना को उतना जन-समर्थन शायद नहीं था, जितना उनकी जीत में दिखाई देता था। लंबे समय तक सत्ता में रहने के साथ-साथ शेख हसीना और उनकी सरकार में एकाधिकारवाद की प्रवृत्ति भी बढ़ी, जो उनकी कार्यशैली से इंगित भी होती है। ये सारी वजहें प्रदर्शनों को बड़ा और उग्र बनाने में सहायक साबित हुईं।

अगर शेख हसीना ने दमन का सहारा नहीं लिया होता और युवाओं को रजाकार या आतंकवादी कहने के बजाय संवेदनशीलता का परिचय दिया होता, आज उन्हें पद के साथ-साथ देश छोड़कर जाने की नौबत नहीं आती तथा बांग्लादेश भी अनिश्चितता से बच जाता। इससे पहले भी बांग्लादेश में जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उनमें भी जमात, पाकिस्तान-समर्थक गुटों और कट्टरपंथियों की भागीदारी होती थी। वैसा इस आंदोलन में भी हुआ होगा। पर इतना बड़ा आंदोलन व्यापक जन समर्थन के बिना संभव नहीं है। यह शेख हसीना को समझना चाहिए था। बहुत से पूर्व सेना अधिकारी और कला जगत से जुड़े लोगों ने भी छात्रों-युवाओं का समर्थन किया है।

बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और उसके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। ऐसे में वहां के घटनाक्रम पर भारत सरकार की नजर होना स्वाभाविक है, पर हमें किसी तरह का अनुमान लगाने या निराधार प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। खबरों के अनुसार, बांग्लादेश की कपड़ों की हजारों फैक्ट्रियां बंद हैं। भारत और बांग्लादेश व्यापार निरंतर बढ़ता गया है। अगर वहां अस्थिरता बढ़ती है, तो द्विपक्षीय कारोबार पर असर पड़ सकता है।

पूरे देश में सड़कों पर घुमंतु पशुओं का मुद्दा संसद में उठा

कोरबा। लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने सदन में पशुधन विकास पर अपनी बात प्रमुखता से रखी। उन्होंने अपने उद्बोधन की शुरूआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उन पंक्तियों से की जिसमें कहा गया कि - किसी राष्ट्र की महानता व उसकी नैतिक उन्नति का अंदाजा हम वहाँ के पशुओं के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते है।

सांसद ने कहा कि भारत की 80 प्रतिशत आबादी पशु पालन के व्यवसाय पर निर्भर है किंतु इन पशुओं के संरक्षण और टीकाकरण के लिए जिस गति से कार्य होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। विभिन्न राज्यों में रोगों से बचाव के लिए पहले दौर में कोई टीकाकरण नहीं हुए। भारत में वर्ष 2021-22 में त्वचा रोग का प्रकोप से कई मवेशी मारे गए। विभाग द्वारा मवेशियों का शारीरिक टीकाकरण लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करनी चाहिए और टीकाकरण के लिए पर्याप्त जनशक्ति की भर्ती व प्रशिक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। सांसद ने कहा कि विभाग ने 2024-25 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो 700 करोड़ खर्च का बजट रखा है वह 2023-24 की तुलना में 19 प्रतिशत कम है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए काफी नहीं है। भारतीय गौवंश के विकास के लिए, गौवंश नस्ल सुधार करने के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित करने की जरूरत है। कृत्रिम गर्भाधान को प्रोत्साहित करने पर काम होना चाहिए। विलुप्ति के कगार

पर पहुंचने वाले पशुओं के संरक्षण की आवश्यकता है, इस संदर्भ में बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

सांसद ने कहा कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में पशु चिकित्सालयों की स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। पशु चिकित्सालयों का उन्नयन और पशु चिकित्सकों की नियुक्ति के साथ पर्याप्त दवाईयां और संसाधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दुग्ध उत्पादन में साल-दर-साल वृद्धि होने की बजाय यह घट रहा है। इससे प्रतीत होता है कि पशु आहारों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में कमी आई है। विश्व गुरू कहलाने वाला भारत दूसरे देशों से पशुआहार ले रहा है जो आश्चर्यजनक है। सरकार को चाहिए कि पशुपालकों को उचित गुणवत्ता का पशुआहार, चारा और दाना उपलब्ध कराए।

सांसद ने पूछा कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में सडक़ों पर घूमने वाले मवेशियों, किसानों के खेत-खलिहान को नुकसान पहंचा रहे पशुओं के लिए क्या प्रावधान किया गया है? सडक़ों पर घूम रहे पशुओं की वजह से मानव और पशुओं का जीवन संकट में आ गया है इसलिए सभी राज्यों में निराश्रित पशुओं के लिए शेल्टर का प्रावधान होना चाहिए। आये दिन गौ वंशों की तस्करी, उन्हें काट कर बेचने व बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाली खबरें मन को विचलित करती हैं। गौवंश की रक्षा के लिए सरकार भले ही बड़े-बड़े दावे करती हो लेकिन जमीनी हकीकत इन मामलों से बयां होती हैं। मेरा आग्रह है कि कानूनों का कठोरता से पालन कराया जाए।

सांसद ने कहा कि मत्स्य पालन कार्य कर रहे हितग्राहियों और छोटे-छोटे तालाबों में मत्स्य पालन कर जीविकोपार्जन कर रहे किसानों को लाभ और आर्थिक उत्थान, महिलाओं और पुरूषों को इन योजनाओं से जोडकर् स्वावलंबी बनाने की दिशा में अधिकांश क्षेत्रों में कार्य नगण्य हैं। कोरबा लोकसभा अंतर्गत मिनीमाता हसदेव बांगो बांध के पानी से विद्युत संयंत्रों की सांस तो चल रही है और छग ही नहीं अन्य प्रदेश भी रौशन हो रहे हैं लेकिन इनसे प्रभावित किसानों व ग्रामीणों के आर्थिक उन्नति नगण्य है। इसके लिए विशेष कार्ययोजना की जरूरत है जिससे प्रभावितों को मत्स्य पालन, झींगा पालन का लाभ मिल सके।

जब बेटी बनी रक्षक, जगदलपुर में आठ बंदूकधारियों से भिड़ी

■ **पिता पर कुल्हाड़ी से हमला, ऐसे बचाई जान**

जगदलपुर। नारायणपुर जिले के झारा गांव में बीती रात एक 17 वर्षीय बेटी अपने पिता को आठ बंदूकधारियों से घिरा देखने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। पिता को कुल्हाड़ी मारने के बाद भी दूसरा वार करने से पहले ही उनके सामने अड़ गई। कुल्हाड़ी को छीनकर फेंकने के साथ ही शोर मचा दिया। जिसके बाद आसपास के लोग घर आ पहुंचे, जहां आठ बंदूकधारी मौके से फरार हो गए। घायल को बेहतर उपचार के लिए मेकाज लाया गया।

मामले की जानकारी में बताया गया कि नारायणपुर जिले के झारागांव में बीती रात घर में मौजूद ग्रामीण को अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा हाथ में रखे कुल्हाड़ी से गले पर हमला कर दिया। घटना के तत्काल बाद ग्रामीण की बेटी ने अपने साहस का परिचय देते हुए पिता को बचाते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल नारायणपुर ले गई। वहां से ग्रामीण की खराब हालत को देखते हुए उसे मेकाज रेफर किया गया है।

मामले की जानकारी देते हुए घायल ग्रामीण सोमधर कोर्राम 50 वर्ष की बेटी सुशीला कोर्राम ने बताया कि शाम को पिता खेत गए हुए थे। उसी समय शाम को मां सुदनी अपने घर के बगल में गई हुई थी, तभी शाम 6 बजे 8 अज्ञात बंदूकधारी आये, आने के बाद पिता के बारे में जानकारी लेने के बाद चले गए।

जैसे ही पिता घर पहुंचे तो बेटी ने इसके बाद बाजू घर चली गई। रात करीब सात बजे वापस अज्ञात लोग आए और पिता से बात करने के साथ ही हाथ में रखे कुल्हाड़ी से गले में वार कर दिया। इसी दौरान बगल घर गई बेटी भी वापस आ गई और अज्ञात लोगों के हाथ में पकड़े कुल्हाड़ी को छीनकर फेंकते हुए आवाज लगाई। जिसके बाद आसपास के लोग घर पहुंच गए। जहां से उसे जिला अस्पताल नारायणपुर फिर मेकाज लाया गया। जहां उसका उपचार जारी है।

कमरा एक, कक्षाएं पांच, तीन साल से नहीं सुधरा स्कूल का जर्जर भवन

छात्रों के साथ शिक्षक भी हो रहे परेशान

भानुप्रतापपुर/कांकेर। प्राथमिक शाला का भवन जर्जर हो गया है। आलम यह है कि कक्षा पहली से लेकर पांचवीं तक की पढ़ाई एक ही कमरे में हो रही है। ऐसी स्थिति में केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी परेशानी रही है। इसे भी पढ़ें = महादेव सट्टा एप पर ्र्र्र्र का एक्शन जारी, भिलाई में चार ठिकानों पर छापेमारी, दो को लिया हिरासत मेंञ

मामला कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विकासखंड के ग्राम भैसमुंडी का है, जहां पिछले 3 वर्षों से प्राथमिक शाला के जर्जर भवन के निर्माण की मांग के बाद भी प्रशासन ने कोई प्रयास नहीं किया। जिसका खामियाजा गांव के नौनिहालों को भुगतना पड़ रहा है। जर्जर भवन के कारण पालक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं।

आलम यह है कि स्कूल के कार्यालय के दस्तावेज बचाने के लिए भवन पर तालपत्री ढंककर रखा गया है। वहीं बच्चों को अनहोनी की आशंका के चलते एक अतिरिक्त कक्ष में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। कक्षा पहली से पांचवीं तक की पढ़ाई एक ही कक्ष में लगाई जा रही है, इससे पदस्थ तीन शिक्षकों और विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

संस्था के प्रधान पाठक केशव राम मंडावी ने बताया कि लगातार हर स्तर पर प्रयास किया जा चुका है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्टाफ को भी पढ़ाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं इस पर भानुप्रतापपुर एसडीएम आस्था राजपूत ने कहा कि भवन मरम्मत के लिए स्टीमेट भेजा गया है। पता कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सिपाही रक्षा सूत्र : फौजियों के लिए छात्राओं ने बनाई राखी

■ **कहा- सूनी नहीं रहेगी हमारे भाइयों की कलाई**

लोरमी। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे देश के फौजी भाइयों के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों, स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों की ओर से राखी, एक चिठ्ठी और अपने आंगन की एक चुटकी मिट्टी भेजी जा रही है, जिससे किसी भी फौजी भाई की कलाई सूनी न रहे। इसी तारतम्य में मुंगेली जिले के लोरमी स्थित गुरुद्वारा चौक में रक्षासूत्र संकलन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

बता दें कि देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात सिपाहियों के हाथों की कलाई सूनी ना रहे, इसके लिए छत्तीसगढ़ में एक विशेष अभियान 'सिपाही रक्षा सूत्र' चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 2023 में 6 लाख 71 हजार राखियां जवानों के लिए भेजी गई थी। वहीं इस वर्ष भी 19 अगस्त को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन पर्व के पहले ही जवानों के लिए अब तक 8 लाख से अधिक राखियां अनेक स्कूलों से संकलन कर लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, तिरंगा सिपाही और मेरा देश स्लोगन के तहत पूर्व सैनिक संगठन के सिपाही, पूर्व सैनिक महासभा एवं सभी राष्ट्रभक्त संगठनों का भारतीय सेना के लिए सम्मानपूर्ण व भावनात्मक अभियान के तहत स्कूली बच्चों सहित अनेक संगठनों की बहनों द्वारा राखी एकत्रित की जा रही है। इस कड़ी में लोरमी स्थित गुरुद्वारा चौक में रक्षासूत्र संकलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी

संख्या में बहनों के अलावा स्कूली छात्रा सहित क्षेत्र के राष्ट्रभक्त उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मौजूद पूर्व सैनिक सिपाही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह राणा ने बताया कि यह अभियान देश के सैनिकों से जुड़ा हुआ है। बहनों के द्वारा बनाई गई राखियों को एकत्रित कर दिल्ली स्थित आर्मी हेड क्वार्टर भेजा जाएगा, जहां मुख्य रूप से भाई-बहन की मिशाल पेश करते हुए एक चिट्ठी, मिट्टी और एक रक्षा सूत्र यह तीनों को मिलकर ही सिपाही रक्षा सूत्र बनता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने भी सभी स्कूलों को राखी एकत्रित करने का निर्देश भी जारी किया है।

इस अवसर पर बोड़तरा स्कूल की छात्रा राधिका हाटले ने कहा कि जो सिपाही हमारे देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात हैं, उनके हाथ की कलाई खाली ना रहे जिसके चलते हम सब रक्षा सूत्र भेजने का काम कर रहे हैं। हम कामना करते हैं कि सभी सैनिक भाई हमेशा सलामत रहे और देश की रक्षा में लगे रहें। इस अवसर पर पूर्व सैनिक सिपाही संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष साहू, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष वर्षा सिंह ठाकुर सहित अन्य सैनिक शामिल रहे।

डॉक्टर को पॉलिसी के नाम पर लगा चूना 14 लाख ठगे जाने के बाद आया होश

भिलाई। स्टील सिटी में पॉलिसी के नाम पर डॉक्टर से ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज किया है।भिलाई नगर पुलिस के मुताबिक सेक्टर 10 निवासी शिशुरोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास वर्मा का पावर हाउस नंदिनी रोड में क्लीनिक है।जिन्होंने थाने में आकर शिकायत दी है।

पीड़ित विकास वर्मा की माने तो रवि झा नामक शख्स ने उन्हें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की ओर से कॉल किया।रवि झा ने कॉल के दौरान डॉक्टर को अलग-अलग कंपनियों के पॉलिसी में पैसा लगाने की स्कीम बताई।इस दौरान रवि झा ने बताया कि वो यदि अलग-अलग पॉलिसी में वन टाइम इनवेस्टमेंट करते हैं तो कुछ सालों बाद उन्हें ना सिर्फ मुनाफा होगा बल्कि पॉलिसी से मिलने वाले बोनस का भी लाभ मिलेगा।

भिलाई नगर टीआई राजकुमार लहरे ने बताया कि विकास वर्मा को झांसे में लेने के लिए रवि झा ने अपने सीनियर मैनेजेर से बात भी करवाई ।फोन पर संबंधित सीनियर अधिकारी ने अपना नाम बंसल बताया। बंसल ने विकास को बताया कि उन्हें किन पॉलिसी में निवेश करना चाहिए।लुभावने स्कीम और जल्दी रकम वापसी के चक्कर में विकास को जरा भी समझ में नहीं आया कि वो ठगी का शिकार हो सकता है।लिहाजा विकास ने एक अनजान कॉल पर भरोसा करते हुए संबंधित व्यक्ति के बताई हुई

पॉलिसी में निवेश करना शुरु कर दिया।

विकास ने कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस 99 हजार 275, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में 79 हजार 999 रुपए, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस 90 हजार 915, कुजैलिन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 41 हजार 300, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 41 हजार 715, आदित्य बिडला हेल्थ डायरेक्ट सीसीए 48 हजार 590, निवाबुपा डायरेक्ट बिजनेस 51 हजार 336, आदित्य बिड़ला हेल्थ डायरेक्ट सीसीए 99 हजार 434, केयर हेल्थ इंस्योरेंस लिमिटेड में 92 हजार 706 कुल 6 लाख 45 हजार 270 की बीमा पॉलिसी कराई।लेकिन जब इन सभी पॉलिसियों के बॉन्ड पेपर और रिसिप्ट रवि झा से मांगा गया तो वो आनाकानी करने लगा।आखिरकार रवि के दिए नंबरों पर बात होनी बंद हो गई। इन सब पॉलिसियों में पैसा लगाने के बाद भी एजेंट ने कुछ नही किया और समय बीतता गया। फिर मार्च 2023 में वेद प्रकाश अरोड़ा नामक शख्स का विकास वर्मा के पास कॉल आया। प्रकाश बताया कि एनपीसीआई में सरकार से नियुक्त हुए हैं। वो बीमा पॉलिसियों के एवज में पैसा दिलवा देंगे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नगर में डायरिया ने दी दस्तक स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

तखतपुर। नगर में डायरिया ने दस्तक दे दी है। तखतपुर के वार्ड क्रमांक 12 में दो बच्चे डायरिया से पीड़ित मिले हैं। दोनों को लगातार उल्टी और दस्त हो रहा था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों बच्चों का इलाज चल रहा। डॉक्टर ने स्थिति को सामान्य बताया है। वार्ड में फैली गंदगी को डायरिया का प्रमुख कारण बताया जा रहा। बता दें कि वार्ड क्रमांक 12 में गंदगी पसरी हुई है। वार्डवासी गंदगी के बीच जीवन जीने में मजबूर हैं। साफ-सफाई में नगर पालिका कोई सुध नहीं ले रहा। कचरे की ढेर सहित जल भराव के बीच लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे। वहीं अब डायरिया और मलेरिया के शिकार हो रहे। तखतपुर में डायरिया के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्थिति का जायजा लेने खंड चिकित्सा अधिकारी सहित पूरा अमला वार्ड क्रमांक 12 पहुंचे हैं। एसडीएम सहित स्वास्थ्य अमले को वार्ड में गंदगी और जलभराव के बीच सर्वे करने में काफी परेशानी हुई। बीएमओ उमेश साहू ने बताया हालात बेहतर है।

बांस के करील से गुलजार हुआ बस्तर का बाजार

जगदलपुर। बस्तर में घने जंगल में बांस की उपलब्धता अधिक है। मानसून में बांस के जड़ से निकलने वाले नन्हे कोपलों (करील) को स्थानीय आदिवासी रहवासी मार्केट में बेच रहे हैं। वन विभाग ने इस पर कार्रवाई करते हुए एक महीने में 4 क्विंटल से अधिक जब्ती की है। बस्तर के स्थानीय लोग बांस के करील को 'बास्ता' कहते हैं। मानसूम के दिनों में बस्तर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक साप्ताहिक बाजार व सामान्य बाजारों में स्थानीय आदिवासी बेचने के लिए बड़ी संख्या में लाते हैं। करील को तोड़ने से बांस के विकास पर होने वाले असर को देखते हुए इसकी कटाई पर रोक लगाई गई है। ऐसे में बाजार में बेचने के लिए लाए जा रहे करील की जब्ती कार्रवाई की गई है। इसी कड़ी में वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने जगदलपुर शहर के संजय मार्केट से करीब डेढ़ क्विंटल करील (बास्ता) जब्त किया गया। मानसून की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 4 क्विंटल से अधिक बास्ता जब्ती कर बेचने वालों पर आवश्यक कार्रवाई की गई है।

पेट्रोल पंप संचालक से लिफ्ट मांगकर लूट लिए 6 लाख रु।

कोरबा। मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे पेट्रोल पंप संचालक पर जानलेवा हमला कर 6 लाख रुपेय की लूट का मामला सामने आया है। ये वारदात कोरबा के वनांचल थाना करतला क्षेत्र की है। घटना को कोरबा और सक्ति जिले के बॉर्डर पर अंजाम दिया गया है। सक्ति निवासी संतोष गोयल रामपुर स्थित पेट्रोल पंप के संचालक हैं। वो रोज की तरह शाम को पूरे दिन की बिक्री की रकम लेकर अपने घर वापस लौट रहे थे। सोमवार को संतोष गोयल पेट्रोल पंप पहुंचे और कामकाज खत्म करने के बाद बैग में 6 लाख रुपए लेकर अपने घर सक्ति के लिए रवाना हुए। इसी बीच कोरबा-सकती बॉर्डर पर एक सुनसान जगह पर युवक ने लिफ्ट के बहाने उन्हें रोकने का प्रयास किया। जब वह नहीं रुके तो डंडे से हमला कर दिया। लुटेरों की संख्या एक से ज्यादा थी। संतोष गोयल को हमले के बाद रुकना पड़ा और फिर बैग में रखे रकम को छीनाझपटी के बाद लुटेरे, लूटने में कामयाब रहे। व्यवसाई के साथ मारपीट और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे फरार हो गए।

युवक का कार में अपहरण के बाद पिटाई, वीडियो वायरल

बिलासपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक युवक का उसी के दोस्तों ने अपहरण कर लिया। इसके बाद युवक के साथ कार में मारपीट की गई। इस केस में हैरानी की बात ये है कि ये सारा कुछ सोशल मीडिया में लाइव चल रहा था। युवक के दोस्त उसे उसी की कार में पीट रहे थे और लोग इस वीडियो को देखकर अपनी राय दे रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद युवक के माता पिता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराने की कोशिश की,लेकिन पुलिस ने मामला ये कहते हुए दर्ज नहीं किया कि दोनों ही पक्षों में समझौता हो चुका है। बाद में पुलिस ने इस केस में एक युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। बिलासपुर में गुंडागर्दी किस कदर हावी है इस बात की बानगी बीते दिनों देखने को मिली।जब एक युवक को उसी के दोस्तों ने कार से अगवा किया। फिर चलती कार में उसकी पिटाई का वीडियो वायरल किया। इस केस में पीड़ित युवक तनय अग्रवाल और आरोपी अनुराग ठाकुर दोनों एक दूसरे को जानते हैं।

एनएमडीसी स्टील प्लांट में शॉर्ट सर्किट से चार झुलसे

जगदलपुर। जगदलपुर के नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील प्लांट में टनल फर्नेश कंट्रोल रूम में शॉर्ट सर्किट से चार कर्मचारी झुलस गए। इनमें दो कर्मचारियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रायपुर बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। दो कर्मचारियों का इलाज जगदलपुर के महारानी अस्पताल के बर्न यूनिट में किया जा रहा है। प्लांट के भीतर एक बार और भी इसी तरह का हादसा हुआ था। जहां गर्म भाप के रिसाव से चार कर्मचारी झुलस गए थे। मौजूदा हादसा प्लांट एरिया के भीतर टनल फर्नेस कंट्रोल रूम में ब्रेकर मेंटेनेंस के काम के दौरान हुआ। यहां इस काम में एनएमडीसी ने दो निजी कंपनियों के कर्मचारी को तैनात कर रखा था। इसी दौरान यूनिट में शॉर्ट सर्किट हो गया और इसकी वजह से भीषण विस्फोट भी हुआ। इस विस्फोट और शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से वहां मेंटेनेंस में काम कर रहे सीनियर टेक्नीशियन तापस नायक, सीमेंस कंपनी के महेंद्र कुमार, लहरे सिंह, इंटरप्राइजेज के देवेंद्र नाग व सीमेंस कंपनी के अमरेंद्र कुमार चौधरी बुरी तरह झुलस गए।

जशपुर में जंगली हाथियों का आधी रात को हमला

जशपुर। जशपुर जिले में इन दिनों हाथियों का इंसानी बस्तियों में आना-जाना बढ़ गया है, जिससे इंसानों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। बीते एक सप्ताह में हाथियों के हमलों में तीन लोगों की जान जा चुकी है। जबकि तमाम जागरूकता प्रयासों के बावजूद हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का अनाज की तलाश में गांवों में घुसना इन हमलों का प्रमुख कारण है।

ताजा घटना बादलखोल अभ्यारण्य के बुटंगा पंचायत के कोरवा बहुल गांव रंगपुर की है। जहां बीती रात एक हाथी ने कोहराम मचाया। दरअसल, आधी रात को दल से बिछड़ा एक हाथी गांव में घुस आया और कोटवार बुधराम का मकान तोड़ दिया। हाथी के आने की सूचना पर ग्रामीण इकट्ठा होकर उसे भगाने की कोशिश करने लगे।

इसी दौरान हाथी ने पहाड़ी कोरवा नरेश राम को देखा और उसे दौड़ाने लगा। नरेश अपनी जान बचाने के लिए घर में घुस गया, लेकिन गुस्साए हाथी ने

उसका घर तोड़ दिया। ग्रामीणों के हल्ला मचाने पर हाथी जंगल की ओर चले गए। जिससे नरेश, उसकी पत्नी और दो बच्चों की जान बच गई।नरेश राम ने अमर उजाला को बताया को कि अभी बरसात हो रही है और हाथी ने घर उजाड़ दिया है,ऐसे में हमारा जीना मुश्किल हो गया है।

इस बढ़ती समस्या को देखते हुए स्थानीय लोगों ने सरकार और वन विभाग से अपील की है कि हाथियों के हमलों से निपटने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

नगर पंचायत जरहागांव के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष समेत सदस्यों की समिति गठित

मुंगेली। हाल ही अस्तित्व में आए जिले के नवगठित नगर पंचायत जरहागांव के अध्यक्ष -उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की समिति का गठन किया गया है। इसे लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया गया, जिसे छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। जारी

अधिसूचना में कहा गया है कि नगर पंचायत जरहागांव की परिषद के कृत्यों के संचालन के लिए आगामी आदेश पर्यंत तक यह प्रभावशील रहेगा। बहरहाल नवगठित नगर पंचायत जरहागांव के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वेदप्रकाश कश्यप ,उपाध्यक्ष संतोष साहू एवं सदस्य रमाकांत कश्यप, कृष्णा जायसवाल, अंजोर दास बंजारे, अनिता कश्यप, विष्णु जायसवाल को मनोनीत किया गया है। इधर नगर वासियों में अब खुशी का माहौल है। ग्राम पंचायत जरहागांव अब नगर पंचायत जरहागांव अध्यक्ष उपाध्यक्ष के मनोनीत किए जाने के बाद पूर्ण रूप से अस्तित्व में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले यहां केवल कुछ माह पूर्व से सीएमओ की पोस्टिंग जरूर की है, मगर वार्डों के परिसीमन के अलावा अब तक नगर विकास का कोई भी काम नहीं हो पाया था। अब लोगों का कहना है कि तेजी से नगर क्षेत्र का विकास होगा।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में डेंटल फ्लोरोसिसि का मामला, सरकार से 2 हफ्ते में शपथपत्र मांगा

बिलासपुर। गरियाबंद जिले के गांवों में बच्चे डेंटल फ्लोरोसिसि का शिकार हो रहे हैं। यह बीमारी पानी में फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा से होती है। इसे कंट्रोल करने के लिए जिले के 40 गांवों में 6 करोड़ की लागत से प्लांट तो लगाए गए लेकिन वह कुछ महीने में ही बंद हो गए।

हाईकोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया और राज्य सरकार को नोटिस भेजा। नोटिस के बाद अपने जवाब में शासन की ओर से कहा गया कि इस मामले में जानकारी लेकर उचित कार्रवाई होगी और जवाब पेश किया जाएगा। कोर्ट ने सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग, को 2 हफ्ते के अंदर व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।

गरियाबंद जिले के प्रभावित गांवों में हर साल 100 से ज्यादा स्कूली छात्रों को डेंटल फ्लोरोसिस होता है। फिलहाल, इन गांवों में 50 से 60 बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस से ग्रसित मिल रहे हैं। देवभोग ब्लॉक के गांवों में कुल पीड़ितों की संख्या 2 हजार से भी ज्यादा है। साल 2016 में शासन-प्रशासन को जांच में फ्लोराइड ज्यादा होने की जानकारी लगी। देवभोग ब्लॉक के 40 गांव के स्कूलों में जो पेयजल सप्लाई हो रही है वहां 8 गुना तक ज्यादा फ्लोराइड था। प्रशासन ने कार्य योजना बना कर सभी प्रभावित स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाने का फैसला लिया। प्लांट तो लगाए गए लेकिन कुछ ही दिनों में बंद हो गए। इस मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट में हो रही।

संक्षिप्त समाचार

विधानसभा अध्यक्ष की फटकार पर कलेक्टरों को भेजी चिट्ठी

रायपुर। दिवंगत विधायकों की सूचना समय पर नहीं मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह द्वारा लगाई गई शासन को फटकार का असर हुआ है। मंत्रालय से कलेक्टरों को पत्र जारी कर भविष्य में त्रुटि न होने की चेतावनी दी गई है। पत्र के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया है। मामला विधानसभा के मानसून सत्र का है, जब सत्र के अंतिम दिन मनेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक विजय सिंह के निधन की सूचना मिली थी। इस पर कांग्रेस और भाजपा दोनों पक्षों के विधायकों के कड़े एतराज के बाद स्पीकर डॉ। सिंह ने भी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने यह व्यवस्था सुधारने शासन को निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि यह देखने में आया है कि कई बार इस तरह की सूचना देने में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही दिखाई पड़ती है, इसलिए राज्य शासन इसे गंभीरता से ले। सर्कुलर में कहा गया है कि वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, संसद सदस्य लोकसभा व राज्य आदि के बारे में जानकारी मिलते ही तत्काल विधानसभा सचिवालय को अवगत कराया जाए। इसमें छत्तीसगढ़ व अविभाजित मध्यप्रदेश के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। दिवंगत विधायक सिंह को लेकर जीएडी ने कहा है कि ऐसा लगता है यह प्रभावी व्यवस्था में खामी का नतीजा है। यह उचित नहीं है।

आदिवासी युवक के साथ अभद्र व्यवहार के आरोप में भाजपा नेता पार्टी से निष्कासित

रायपुर। भाजपा ने अपने नेता और युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह को पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने अजय सिंह के द्वारा भैरमगढ़ में आदिवासी युवक के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के मामले में यह कार्रवाई की है। बीजेपी की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अजय सिंह पर एक आदिवासी युवक के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप है। इस विवाद के चलते अजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। यह पार्टी की अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और इसे गंभीरता से लेते हुए पार्टी ने अजय सिंह निष्कासित कर दिया है।

रायपुर रेलवे स्टेशन की लिफ्ट में फंसे यात्री, फोड़ा गया कांच

रायपुर। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 में मौजूद लिफ्ट के अंदर आज कुछ यात्री फंस गए। घटना के बाद यात्री काफी देर तक अंदर डरे सहमे रहे। इसके बाद लिफ्ट का कांच तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। घटना के रायपुर रेलवे स्टेशन की लिफ्ट के मेंटेनेंस पर सवाल उठ रहे है। यात्रियों का आरोप है कि रेलवे के अधिकारी समय-समय पर यदि लिफ्ट की मेंटेंनस करवाते तो शायद ऐसे हादसे नहीं होते। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक लिफ्ट से यात्रियों को निकलाने की काफी कोशिश की गई। लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली तो लिफ्ट के कांच को तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया।

तीन साल के बच्चे को तेंदुआ ने उठाया जंगल में अब तक नहीं मिला सुराग

धमतरी। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में इन दिनों तेंदुआ का आतंक है। ताजा घटनाक्रम में तेंदुआ एक बच्चे को उठाकर ले गया है। सिहावा थाना क्षेत्र का कोरमूड वन परिक्षेत्र बीरगुड़ी गांव की ये पूरी घटना है। जहां रविवार की रात तीन साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ सो रहा था। लेकिन जब आधी रात को उसके पिता की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसका बेटा पास में नहीं है। सुबह होने पर जब घर के आसपास ढूंढा गया तो परिवार वाले सहम गए। क्योंकि उन्हें पास ही तेंदुआ के पैरों के निशान दिखाई दिए। परिवार को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उनके बच्चे के साथ अनहोनी हो गई है।गांव में बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले जाने की जैसे ही बात फैली वैसे ही सभी बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चले गए। गांव में तेंदुआ आने की सूचना मिलने के बाद वनविभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है।जहां पर वो तेंदुआ को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। वनविभाग की टीम ग्रामीणों के साथ मिलकर बच्चे को तलाश कर रही है। लेकिन अभी तक मासूम की कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी है।

महादेव सट्टा एप : एसीबी और ईओडब्ल्यू ने की छापेमारी

दुर्ग। दुर्ग में एसीबी और ईवोडब्ल्यू की टीम ने मंगलवार को छापेमारी कर ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप का पैनल चलाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को एसीबी की टीम रायपुर ले गई है। उनसे पूछताछ की जा रही है। एसीबी की टीम ने ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप के कारोबार करने वाले पर भिलाई के कई ठिकानों छापामार कार्यवाही की है। एसीबी की टीम ने चार अलग-अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्यवाही में दुर्ग क्राइम ब्रांच और स्थानी पुलिस से भी मदद ली थी एसीबी और ईवोडब्ल्यू की टीम ने न्यू खुर्सीपार के बंगाली मोहल्ला में रहने वाले विश्वजीत राय और अतुल राय को गिरफ्तार कर एसीबी की टीम ने पाने साथ पुछताछ के लिए रायपुर लेकर चली गई है। वहीं टीम ने भिलाई में फरीदनगर स्थित मोहम्मद सद्दाम के निवास पर भी छापेमारी की लेकिन सद्दाम के घर पर ताला लगा हुआ था। सद्दाम के निवास पर ईडी की टीम भी कार्रवाई कर चुकी है। विश्वजीत रॉय जिम का संचालन करता है और पिछले कुछ महीनों से उसका जिम बंद पड़ा है। जिम बंद करके महादेव सट्टा एप का पैनल का संचालन करना शुरू कर दिया था।

रेडी टू ईट योजना महिला स्वसहायता समूहों को फिर से सौंपने की तैयारी : मुख्यमंत्री

जशपुर। जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि रेडी टू ईट योजना, जिसे भूपेश सरकार के दौरान महिला स्वसहायता समूहों से छीन लिया गया था, अब फिर से इन्हीं समूहों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने यह घोषणा अपने दो दिवसीय जशपुर दौरे के दौरान की। मुख्यमंत्री साय ने सुबह बगिया निवास श्रीराम सदन में 59 कब्जाधारियों को वनभूमि के पट्टे सौंपे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने प्रदेश में नए जिले बनाने की योजना से फिलहाल इंकार किया।

मुख्यमंत्री साय पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 बजे मेगा पालक-शिक्षक बैठक में शामिल होने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बन्दरचूंवा पहुंचे। यहां उन्होंने विद्यार्थियों और उनके पालकों से बातचीत की। यह कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है।

शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने जानकारी दी कि प्रदेश के 5,500 संकुल में पालकों की बैठक आयोजित की जा रही है और 48,000 सरकारी स्कूलों में साल में तीन बार पालकों की बैठक होगी। यह पहली बैठक मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित की गई है। बैठक में पालकों को बच्चों की पढ़ाई के स्तर को बढ़ाने के लिए 12 बिंदुओं पर चर्चा की गई और जानकारी दी गई। बच्चों में पढ़ाई के कारण बढ़ते तनाव को दूर करने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में 20 बोली भाषाओं में पुस्तक बनाने का काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच से कहा कि यहां इस स्कूल में मैं पहले भी आ चुका हूं। मेरी पत्नी हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस यहीं मनाती हैं। शिक्षा का बड़ा महत्व है और विद्वानों ने इसे विकास का मूलमंत्र बताया है। शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को पूर्ण बनाने के लिए जरूरी है। शिक्षा के कारण हमारा देश विश्वगुरु कहलाता था और यहां नालंदा और तक्षशिला में दुनियाभर से विद्यार्थी आते थे।

सीएम ने कहा कि कहा, मैकाले की शिक्षा पद्धति बहुत दिनों तक चली, लेकिन अब समय के साथ बदलते परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, जो युवाओं और बच्चों को डिग्री, संस्कार और रोजगार के लिए कौशल विकास करने का काम करेगी। अब साल में तीन बार शिक्षक-पालक की बैठक होगी। नई शिक्षा नीति में लोकल भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। जशपुर में पीएमश्री योजना के तहत 263 स्कूल शामिल किए गए हैं, जिससे वे स्कूल प्रायवेट स्कूलों की तरह सुविधाओं से लैस होंगे।

मुख्यमंत्री साय ने जशपुर में 500 सीटर और कुनकुरी में 200 सीटर नालंदा परिसर खोलने की घोषणा की। उन्होंने बन्दरचूंवा में सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड, प्राथमिक शाला से छेराघोघरा के लिए स्ट्रीट लाइट, बंदरचुंवा दोनों मंदिरों के जीर्णोद्धार का भी ऐलान किया। इसके अलावा, उन्होंने बन्दरचूंवा में एक मिनी स्टेडियम और छात्रावास को 50 सीट से बढ़ाकर 100 सीट करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री साय ने पालक हरिसेवक की तारीफ करते हुए कहा कि उनका पोता यहीं से पढ़कर एमएससी कर रहा है। उन्होंने कहा, रायपुर में नालंदा परिसर खोला गया है, जहां प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए 24 घंटे खुला रहता है। ऐसे ही नालंदा परिसर 22 जिलों में खोलने जा रहे हैं। इन सभी योजनाओं और घोषणाओं के साथ, मुख्यमंत्री साय ने शिक्षा और विकास के क्षेत्र में व्यापक सुधार और प्रगति का आश्वासन दिया।

कोरोना काल में दवा और उपकरण खरीदी में 2.65 करोड़ का घपला

■ तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर सस्पेंड

रायपुर। राज्य शासन ने कोरोना काल के दौरान साल 2020 में दवा और उपकरणों की खरीदी में हुए करोड़ों के घोटाले के मामले में तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर डॉ. निर्मल वर्मा को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच चल रही थी। दो साल पहले उन्हें इस केस में दोषी पाया गया था। शासन ने साल 2020 में दवा, लैब सामग्री और उपकरण खरीदी में 2 करोड़ 65 लाख 29 हजार 296 रुपए की अनियमितता के मामले में कार्रवाई की है। फिलहाल वर्मा पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पीएसएम विभाग के एचओडी हैं।

निलंबन के दौरान उन्हें मेडिकल कॉलेज कांकेर में अटैच किया गया है। जांच समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि इन खरीदारियों में करीब 2.65 करोड़ रुपये की अनियमितताएं पाई गईं है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से गठित जांच समिति ने इस मामले की गहन जांच की थी और पाया कि उस दौरान चिकित्सा शिक्षा संचालक के रूप में संविदा पर कार्यरत डॉ. एसएल आदिले और वित्तीय अधिकार रखने वाले डॉ. निर्मल वर्मा ने नियमों का उल्लंघन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में डॉ. वर्मा को दोषी करार दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी।

कोरोना खत्म होने के बाद इस मामले की शिकायत की गई थी। इस आधार पर चिकित्सा शिक्षा विभाग स्तर पर गठित की गई कमेटी ने मामले की जांच की तो करीब 2.65 करोड़ की अनियमितता उजागर हुआ था। मामले में तात्कालीन एडीशनल डायरेक्टर डॉ. निर्मल वर्मा को दोषी पाया गया था। उस दौरान चिकित्सा शिक्षा संचालक के रूप में संविदा आधार पर डॉ. एसएल आदिले कार्यरत थे और वित्तीय अधिकार डॉ.वर्मा के पास थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उन्हें दोषी माना था, जिसके आधार पर कार्यवाही की अनुशंसा की गई थी, हालांकि उस दौरान मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। कुछ समय पहले यह मामला दोबारा चर्चा में आया और शासन ने डा. वर्मा को निलंबित कर दिया है। शासन के नियमानुसार एक लाख की ज्यादा से खरीदी टेंडर से की जाती है, लेकिन डॉ. वर्मा तब डीडीओ भी थे। उन्होंने 2 करोड़ 65 लाख 29 हजार 296 रुपए के क्रय आदेश कोटेशन के आधार पर किया। जांच कमेटी ने इसे घोर वित्तीय उल्लंघन माना था। सस्पेंशन आर्डर में भी खरीदी में घोर वित्तीय अनियमितताएं का उल्लेख है।

केंद्रीय मंत्री उरांव से केदार कश्यप ने जनजातीय विषयों पर की सार्थक चर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वनमंत्री केदार कश्यप अपने एक दिवसीय दिल्ली प्रवास पर हैं। इस दौरान मंगलवार को उन्होंने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव से सौजन्य भेंट कर विभिन्न जनजातीय विषयों पर सार्थक चर्चा की। वनमंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव को जानकारी देते हुए बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर द्वारा लगभग 6.5 लाख आदिवासी परिवारों से वर्ष 2014-15 से लघु वनोपज का क्रय किया जा रहा है। इनके व्यापार में होने वाली हानि की 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक की अवधि में उक्त व्यापार में रुपये 52.18 करोड़ की हानि हुई है, जिसकी 75 प्रतिशत राशि 39.14 करोड़ की प्रतिपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर द्वारा ट्रायफेड को औपचारिकताओं की पूर्ति उपरांत लिखे जाने के बाद भी उक्त राशि अप्राप्त है। वनमंत्री कश्यप ने केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव से आग्रह किया है कि उक्त कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कार्य पूंजी की भी राज्य को आवश्यकता है। मंत्री कश्यप ने उन्हें छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार द्वारा आदिवासियों के हित के किए जा रहे कार्यों से भी अवगत कराया।

कलेक्टर जनदर्शन से ग्रामीणों के उम्मीदों की आस हुई पूरी

■ महज 15 दिनों के भीतर हुआ सारा काम

रायपुर। रायपुर जिला के धनेली गांव के ग्रामीणों की छह साल से रूकी जमीन की रजिस्ट्री महज पखवाड़े से कम समय में हुई। छह साल से जो जमीन रजिस्ट्री विक्रेता की वजह से रूकी थी, वह जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद महज 15 दिनों के भीतर हो गई। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन और उनके नेतृत्व में हो रहे त्वरित काम की सरहाना की। ग्रामीणों ने कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह से मुलाकात कर प्रसन्नता जाहिर की और आभार जताया।

वर्ष 2017 में धनेली (सांकरा) के ग्रामीण दादूलाल यादव, अमृतलाल साहू, गुलाब सिंह सहित 30 ग्रामीणों ने खुद का मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने का सोचा, तब उनका संपर्क एक स्थानीय माध्यम से हुआ। जिसमें अपनी जमीन बताकर सौदा किया। ग्रामीण दादू लाल का कहना है कि विक्रय ने अपनी जमीन दिखाकर इकरारनामा कराया, प्रत्येक प्लॉट की कीमत करीब ढ़ाई से तीन लाख रूपए थी। सभी ग्रामीणों द्वारा कुछ पैसे एडवांस में दिए गए, वहां जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर

रहा था, तभी कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के जनदर्शन में पहुंचे।

कलेक्टर के समक्ष जमीन रजिस्ट्री कराने का आग्रह किया। कलेक्टर ने रायपुर एसडीएम नंदकुमार चैबे को निर्देशित किया। संबंधित अनुविभाग कार्यालय द्वारा प्रक्रियाओं को जल्द पूर्ण कराया गया और बाधाएं भी दूर की गई, इससे जल्द रास्ता निकला और उनकी जमीन की रजिस्ट्री हो गई। अब ग्रामीण अपने आशियाने के सपनों को साकार कर सकेंगे। लंबे समय से आशियाना का सपना संजोए ग्रामीणों का अब अपना खुद का घर होगा।

छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते से उद्योग बंद

कांग्रेस बोली- ये कैसी सरकार?, भाजपा राज में व्यापारी हो रहे परेशान

रायपुर। कांग्रेस ने उद्योगों के बंद को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब से राज्य में भाजपा सरकार बनी है तब से वह उद्योग व्यापार को चौपट करने वाला निर्णय ले रही है। जिन व्यापारियों उद्योगपतियों को दिये जाने वाले टैक्स के पैसे से सरकार विकास और राहत के काम करती है। उन्हीं व्यापारियों को परेशान किया जाना गलत है? आरोप लगाया कि सात महीने में लगातार व्यापारियों के यहां सरकार की ओर से जीएसटी के छापेमारी करवाया जा रहा है। बिजली बिल बढ़ोतरी के कारण उद्योगो में एक सप्ताह से तालाबंदी है। 2 लाख मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा नेता की ओर से व्यापारियों को टैक्स चोर कहना निंदनीय है ये वही व्यापारी हैं, जिनके दिये गए टैक्स से राज्य का खजाना भरता है और विकास कार्य होता है। व्यापारी वर्ग लगातार अनियमितता जीएसटी से परेशान और हताश होकर केंद्र सरकार से कई बार गुहार लगाये हैं। कई सुझाव दिए हैं, लेकिन उसे पर केंद्र सरकार ने अमल नहीं किया है और जो जीएसटी का छापा व्यापारियों के यहां पड़ रहा है। यह सिर्फ भाजपा के वसूली के लिए पड़ रहा हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिस समय जीएसटी लागू किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने जीएसटी के कई स्लैब और इसके कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए थे और पूरे देश में व्यापारी वर्ग भी इसके खिलाफ रहे हैं। जीएसटी के विषय पर अब तक 3000 से अधिक सुधार किया गया है। उसके बावजूद जीएसटी की समस्या निरंतर बनी हुई है। भाजपा नेता जीएसटी को लेकर अपनी केंद्र सरकार की नाकामी को ढकने के लिए अब सीधा-सीधा व्यापारी को ही टैक्स चोर कह रहे हैं, जो कि पूरी तरह से निंदनीय है।

राजस्व मंत्री ने पीएम आवास के हितग्राही को कराया गृह प्रवेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा हरेली त्यौहार के पावन अवसर पर विकासखंड बलौदाबाजार के ग्राम सकरी में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राही को नवनिर्मित आवास का फीता काटकर गृह प्रवेश कराया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सुंदर मकान बनाने पर गिरजाशंकर और उसके परिवार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नवनिर्मित मकान के आंगन में कटहल और अमरुद के पेड़ लगाए। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व संसदीय सचिव डॉ सनम जांगड़े, कलेक्टर दीपक सोनी, सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल उपस्थित थे।

पेशे से राज मिस्त्री हितग्राही गिरजाशंकर ने बताया कि पहले कच्चा मकान था। जिसमें कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता था। पक्का मकान का सपना था, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसी बीच वर्ष 2020- 21 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास स्वीकृत हुआ। पहली किश्त मिलने पर मकान बनाना शुरू किया तीन किश्त में कुल एक लाख बीस हजार रुपये मिले। उन्होंने बताया कि कुछ अपना पैसा लगाकर घर को थोड़ा बड़ा बना लिया। गिरजाशंकर ने बताया कि उनकी पत्नी बुद्धेश्वरी वर्मा को महतारी वंदन योजना के तहत हर माह एक हजार रुपये मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का भी लाभ मिला है।

मंत्री टंकराम वर्मा ने ग्राम सकरी के अमृत सरोवर में जय मां अन्नपूर्णा स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मछली पालन की शुरुआत सरोवर में मछली बीज डालकर किया। उन्होंने मछली पालन को लाभ का व्यवसाय बताते हुए महिलाओं को बेहतर ढंग से मछली पालन करने कहा। महिलाओं ने बताया कि वे इस सरोवर में पहली बार मछली पालन करने जा रही है। मछली पालन विभाग द्वारा अभी 65- 70 नग रोहु, कतला और मृगल मछली प्रतिकात्मक रूप से दिया गया है। कुछ दिन बाद विभाग द्वारा करीब 5000 मछली बीज़ (फिंगर लिंग) दिया जाएगा।

मंत्रालयीन अधिकारियों-कर्मचारियों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

रायपुर। रायपुर में अधिकारी और कर्मचारियों ने 'झन कर इंकार, हमर सुनव सरकार' के नारे के साथ महँगाई भत्ता और एरियर्स समेत सात सूत्रीय मांग को लेकर मंत्रालय से संचालनालय तक मशाल रैली निकाली। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारी राजेश चटर्जी और कमल वर्मा ने बताया कि यह रैली अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि 20-30 अगस्त तक सभी सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 11 सितंबर से जिला, ब्लॉक, तहसील स्तर पर मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा, और 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन होगा।

आज मशाल रैली और चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों ने महँगाई भत्ता, एरियर्स सहित सात सूत्रीय माँगों को जोर-शोर से उठाया और जमकर नारेबाजी की, इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मंत्रालयीन अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

फेडरेशन की सात सूत्रीय मांगें

1. कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से महँगाई भत्ता में 4त्न वृद्धि के साथ 50% महँगाई भत्ता दिया जाए। 2. 1 जुलाई 2019 से लंबित महँगाई भत्ता एरियर्स को जीपीएफ खाते में जमा किया जाए। 3. कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान स्वीकृत किया जाए। 4. कर्मचारियों को केंद्र के समान गृह भाड़ा दिया जाए। 5. अर्जित अवकाश नकदीकरण की सीमा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन की जाए। 6. प्रदेश के लिपिकों के वेतनमान में सुधार किया जाए। 7. संचालनालयीन कर्मचारियों को संचालनालयीन भत्ता और मंत्रालय में प्रवेश के लिए पत्र दिया जाए।

फेडरेशन के पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर उनकी माँगें पूरी नहीं की गईं, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे।

तिरंगा यात्रा पर सियासत, कांग्रेस ने बताया राजनीतिक प्रोपोगंडा

■ भाजपा बोली- टिप्पणी करने में बरतें परहेज

रायपुर। देश-प्रदेश की सियासत का स्तर कहां तक पहुंच गया है इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तिरंगा यात्रा जैसी कवायद पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भाजपा की तिरंगा यात्रा राजनीतिक प्रोपोगंडा करार दिया है। इस पर भाजपा ने कांग्रेस को इस तरह की टिप्पणी से परहेज बरतने को कहा है।

कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि बीजेपी ने तीन रंगों को देश के लिए घातक बताया था। राजनीतिक प्रोपग्रंडा के लिए बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। इस आरोप पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना आ रही है। अगर हर घर में तिरंगा लगे तो क्या खराबी है।

उन्होंने कहा कि हमारे देश का झंडा है। उसको लेकर बीजेपी कार्यक्रम करें, तो इस पर किसी भी कीमत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने के बहुत सारे विषय हैं। देश के सम्मान से जुड़ा है। बहुत अच्छा संदेश है। इस पर राजनीति या टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस पर भी टिप्पणी कर रही है।

सुशील आनंद शुक्ला ने तिरंगा यात्रा के अलावा स्पंज उद्योग द्वारा अडानी को खत लिखने पर कहा कि कुल मिलाकर जो सर्कल था वह पूरा होने की स्थिति पर है। सरकार ने अडानी को ही फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के उद्योगों के बिजली दामों को बढ़ाया था, अब उद्योगपतियों

ने मजबूरी में अडानी को पत्र लिखा है। अडानी और उद्योग के बीच स्ल्ह हो जाएगा। मामला खत्म हो जाएगा।

शुक्ला ने कहा कि लोहा उद्योग व्यापार की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। पिछली सरकार ने बिजली में सब्सिडी दिया था, इस सरकार ने क्यों बढ़ाया, क्यों उनकी बात नहीं मानी जा रही है, बीच के रास्ता क्यों नहीं निकाला जा रहा है।

विधानसभा के अधिकारियों के नाराजगी को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को सिर्फ नाराज ही नहीं होना था। सरकार में बैठे लोगों को उस पर लपेटना था। विधानसभा सर्वोच्च है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में सरकार के कामकाज को सुचारू रूप से चलने में गाइडलाइन देती है। विधानसभा में कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो आपत्तिजनक है। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखना पड़ा है, मतलब सरकार का कार्य प्रणाली क्या है।

राजनीति की गिरती साख किसी से छिपी नहीं रही

राज कुमार सिंह

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में ऐसे असंसदीय आचरण के उदाहरण ज्यादा नहीं मिलेंगे। अपने विशेषाधिकारों के प्रति संवेदनशील रहने वाले सांसदों में ही संसद की गरिमा के प्रति सजगता नजर नहीं आती। चुनावी और राजनीतिक सभाओं में बोले जाने वाले राजनेताओं के बिगड़ैल बोल अब लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में सुनाई पडने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा बिना नाम लिए ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाति पर कटाक्ष करने के कुछ अंशों को आसन द्वारा सदन की कार्रवाई से निकाल देना बताता है कि वे असंसदीय थे, पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उस भाषण की प्रशंसा से साफ है कि अपने सांसदों के आचरण के प्रति दलों का नेतृत्व भी बहुत संवेदनशील नहीं। 18वीं लोकसभा के चुनाव के पहले से ही विपक्ष जाति जनगणना को नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के विरुद्ध मुद्दा बना रहा है। कभी अमीर-गरीब तो कभी विभिन्न वर्गों को ही जाति बता कर भाजपा इसकी काट करती रही है। निकट भविष्य में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यह स्वाभाविक ही है कि हमारे चुनावजीवी राजनीतिक दल और नेता अपने हर उस मुद्दे को धार देते रहेंगे जो उनके पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण कर सकता हो, पर जिस तरह संसदीय गरिमा और सार्वजनिक शिष्टाचार की सीमाएं लांघी जा रही हैं, वह चिंताजनक है। लोकसभा में 29 जुलाई को बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बजट तैयार करने वाले नौकरशाहों में दलित, आदिवासी, ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों की संख्या पर सवाल उठाते हुए कटाक्ष किया कि बजट प्रक्रिया की शुरूआत में जो हलवा बनता और बंटता है, उसके फोटो में तो इन वर्गों का कोई भी अफसर नजर नहीं आ रहा। नेता प्रतिपक्ष ने टिप्पणी की कि दो-तीन प्रतिशत लोग हलवा बनाते हैं और आपस में बांट लेते हैं, शेष आबादी को कुछ नहीं मिल रहा। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सिर पकड़ कर हंसने लगीं तो राहुल ने टिप्पणी की कि मैडम, यह हंसने की बात नहीं है। बजट निर्माण समेत सरकार के हर काम को जातीय प्रतिनिधित्व के नजरिए से देखना कितना उचित है और यह सोच कहां जाकर रुकेगी, यह व्यापक विमर्श का विषय होना चाहिए। राहुल के व्यंग्य बाणों का सत्तापक्ष की ओर से जवाब अपेक्षित ही था, पर उस प्रक्रिया में तमाम मर्यादाएं लांघ जाना भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर से अपेक्षित नहीं था, जो पिछली मोदी सरकार में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं। ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, पर कटाक्ष किया कि जिसकी जाति का पता नहीं, वह गणना कराने की बात करता है। आम व्यवहार में भी ऐसी भाषा पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है। ऐसे में संसद में हंगामा होना ही था। अनुराग के कटाक्ष पर राहुल बोलने के लिए खड़े तो हुए, पर आपत्ति जताने के बजाय कहा कि आप लोग मुझे चाहे जितनी गाली दो, अपमानित करो, पर मैं जाति जनगणना से पीछे हटने वाला नहीं। राहुल ने यह कह कर सबको चौंका दिया कि उन्हें अनुराग से इस टिप्पणी के लिए माफी भी नहीं चाहिए, पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ठाकुर को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने इस तरह किसी की जाति पूछने पर कड़ी आपत्ति जताई और फिर व्यंग्य किया कि इस बार मंत्री न बनाए जाने का दर्द उनके चेहरे पर झलक रहा है। भाजपा ने राहुल गांधी पर ऐसा तीखा कटाक्ष पहली बार नहीं किया है। भाजपा 'युवराज' और 'शहजादा' ही नहीं, 'पप्पू' तक कह कर उनका मजाक उड़ाती रही है, पर लोकसभा में अनुराग की टिप्पणी तमाम हदें पार कर जाने जैसा है। फिर भी संभव था कि दो-चार दिन उनकी आलोचना के बाद टिप्पणी नेताओं के बिगड़े बोल मान कर भुला दी जाती, लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने अनुराग के भाषण को शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जिस तरह उसकी प्रशंसा की, उसने 'इंडिया' गठबंधन, खासकर कांग्रेस को भड़का दिया है। मोदी ने 'एक्स' पर लिखा कि मेरे युवा और ऊर्जावान साथी अनुराग ठाकुर का भाषण अवश्य सुनना चाहिए, जो तथ्यों और व्यंग्य का सही मिश्रण है तथा 'इंडी एलायंस' की गंदी राजनीति को बेनकाब करता है।

हसीना का तख्तापलट भारत के लिए अच्छा नहीं

नीरज कुमार दुबे

बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में जान-माल और लोकतंत्र को भारी नुकसान के बाद आखिरकार शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हो ही गया। देश की कमान अब सेना के पास है और उसने अंतरिम सरकार का गठन करवाने की बात कही है। शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने के लिए बांग्लादेश में जिस तरह का अभियान चलाया गया उसने दूसरे इस्लामिक देशों के सत्ताधारियों की नींद उड़ा दी है। शेख हसीना का सत्ता से बाहर होना कट्टरपंथियों की बहुत बड़ी जीत है। यह जीत दर्शाती है कि दुनिया भर में हावी होते इस्लामिक कट्टरपंथी अब भारत के बगल में भी प्रभावी हो रहे हैं। दुनिया में कई इस्लामिक देश उदारवादी माने जाते हैं अब उन्हें यह खतरा सता रहा है कि यदि कट्टरपंथी उनके यहां भी हावी हुए तो वर्तमान सत्ताधारियों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाकर उन्हें शासन से बाहर किया जा सकता है।

जहां तक शेख हसीना की बात है तो उनके शासनकाल में पहली बार देश में हालात इस कदर बेकाबू हुए कि उन्हें इस्तीफा देकर अपना देश छोड़कर ही भागना पड़ा। शेख हसीना के खिलाफ इस समय नाराजगी भले चरम पर पहुँच चुकी थी लेकिन जब वह 2009 का आम चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बनी थीं तब उनकी लोकप्रियता देखने लायक थी। 2009 के बांग्लादेश चुनाव के नतीजों से सबसे बड़ा झटका शेख हसीना की मुख्य प्रतिद्वंद्वी खालिदा जिया को नहीं बल्कि कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी को लगा था। जमात-ए-इस्लामी वही संगठन है जिसने 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान का पक्ष लिया था। खालिदा जिया की सरकार के दौरान आतंकवादी संगठन बांग्लादेश में खूब फले-फूले थे और कट्टरपंथियों का वहां बोलबाला हुआ करता था। जमात-ए-इस्लामी के भी उस समय 20 सांसद हुआ करते थे। यही नहीं, खालिदा जिया के जमाने में आतंकी तत्व बांग्लादेश की धरती का उपयोग भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाने में किया करते थे। उस समय उल्फा तथा कई अन्य उग्रवादी संगठनों के ठिकाने बांग्लादेश में हुआ करते थे। इस संबंध में जब भी भारत सरकार ने तत्कालीन बांग्लादेश सरकार को कार्रवाई के लिए कहा

तब-तब खालिदा जिया की सरकार कह देती थी कि भारत की ओर से दी जा रही सूचनाएं गलत हैं।

खालिदा जिया ने सत्ता से हटने के बाद काफी प्रयास किया कि वह दोबारा सरकार में लौट सकें लेकिन जनता ने उन्हें हमेशा खारिज किया। खालिदा जिया धीरे-धीरे मुख्यधारा की राजनीति से दूर हो गयीं जिससे ऐसे उत्पाती और आतंकी तत्वों के लिए अस्तित्व बचाने का सवाल खड़ा हो गया जोकि खालिदा जिया के शासन की छत्रछाया में पनपते थे। इन तत्वों ने सरकार के विरोध में योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाया और छात्रों को आगे कर वह अपना उद्देश्य हासिल करने में सफल रहे। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वह वहां के लिए तो घातक है ही साथ ही भारत के लिए भी यह मुश्किल बढ़ने वाली बात है। भारत ने हालांकि बांग्लादेश सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है लेकिन अब देश को चीन और पाकिस्तान की सीमा के अलावा बांग्लादेश सीमा पर भी काफी सावधानी बरतनी होगी। ढाका में दिल्ली समर्थक सरकार का नहीं रहना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है।

हम आपको बता दें कि 2009 में शेख हसीना सरकार के आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में प्रगाढ़ता आई थी। इससे पहले जब शेख हसीना 1996 से 2001 के बीच सत्ता में थीं तब भी भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर रहे थे। शेख हसीना ने बांग्लादेश की कमान संभालने के बाद कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई थी और भारत विरोधी गतिविधियां संचालित कर रहे संगठनों पर भी अंकुश लगाया था। यही नहीं, शेख हसीना बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को भी अक्सर सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाती रहती थीं और उनके धार्मिक आयोजनों में भी शामिल होती थीं। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़ने और हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुँचाये जाने की आशंकाएं बलवती हो रही हैं। पहले भी वहां हिंदुओं पर वीभत्स हमले होते रहे हैं ऐसे में अब उनके लिए खतरा और बढ़ गया है।

वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि शेख हसीना ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भी संकटों से उबारा था लेकिन यह भी तथ्य है कि हाल के वर्षों में खासकर महामारी के बाद से देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के चलते शेख हसीना के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही थी। देखा जाये तो बांग्लादेश में मौजूदा अशांति का कारण सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या नहीं बढ़ना भी है। उस पर से बांग्लादेश सरकार के हालिया आरक्षण संबंधी फैसले से छात्रों में नाराजगी बढ़ गयी थी। इसके अलावा, बांग्लादेश के कपड़ा कारखाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं लेकिन अब यह क्षेत्र सिकुड़ रहा है जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। साथ ही बांग्लादेश में महंगाई के 10 प्रतिशत के आसपास बने रहने, बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार के सिकुड़ते जाने और देश पर विदेशी कर्ज बढ़ते जाने जैसे कई अन्य कारक भी रहे जोकि शेख हसीना सरकार के खिलाफ आम जनता की नाराजगी बढ़ा रहे थे।

उस पर से जब शेख हसीना ने यह कह दिया कि आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोग छात्र नहीं बल्कि इस्लामिक पार्टी, जमात-ए-इस्लामी और मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के लोग थे तो छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। इसके बाद शेख हसीना ने और कड़ा रुख अपनाते हुए कह दिया कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं वे छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं इसलिए सरकार उनके साथ सख्ती से निबटेगी। उनके इस बयान के बाद तो आंदोलनरत छात्रों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया और आखिरकार वह अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल रहे।

बांग्लादेश से जो दृश्य सामने आ रहे हैं वह दर्शा रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों का मकसद सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आवास और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जो हरकतें की हैं वह दर्शा रही हैं कि अब देश अराजकतावादियों के हाथ में चला गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आवास में जिस तरह मस्ती करते या संपत्ति को नुकसान पहुँचाते युवकों का वीडियो सामने आया है उसने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारियों और अफगानिस्तान में तख्तापलट के दौरान सरकारी इमारतों में घुसते तालिबानियों की याद दिला दी है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों को समझना होगा कि मूर्तियों को तोड़ने, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाने और किसी देश के विरोध में अभियान चलाने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं जायेगी। बांग्लादेश में लोकतंत्र के नहीं रहने का सबसे बड़ा खामियाजा यह होगा कि विदेश कर्ज हासिल करने के जो प्रयास किये जा रहे थे, या बांग्लादेश में जो निवेश आने वाला था, अब वह बाधित हो जायेगा। बांग्लादेश में लोकतंत्र के नहीं रहने का खामियाजा यह होगा कि विदेशी सरकारें उसकी मदद करने से कतराएंगी। दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश दूसरे देश की सरकार से ही बातचीत करने या कोई करार करने को वरीयता देता है। सैन्य नियंत्रण वाले देशों से लोकतांत्रिक देश अक्सर दूरी बनाये रखते हैं। बहरहाल, बांग्लादेश की सेना और राष्ट्रपति को चाहिए कि जल्द से जल्द अंतरिम सरकार का गठन किया जाये और संभव हो तो नये चुनाव कराये जाएं। यह सर्वविदित है कि हिंसा किसी मसले का हल नहीं है, लूटपाट और उत्पात से देश को नुकसान ही होगा और पिछले वर्षों में आगे बढ़ने के लिए जो मेहनत की गयी थी उस पर भी पानी फिर जायेगा। इसलिए समय की आवश्यकता है कि बांग्लादेश एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकले।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

अविशिष्ट-क्रम (भाग-3)

गतांक से आगे...

यहां यह कह देना अनुचित न होगा कि पूर्वोक्त क्रम-रहस्थ में जिस पुराण का जो विशिष्ट स्थान नियत किया गया है वह केवल उस पुराण के प्रतिपाद्य विषय की मुख्यता के आधार पर ही किया गया है। वैसे तो प्रत्येक पुराण में प्रसङ्गोपात्त अनेक विषय वर्णित हैं तथा प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति न्याय के अनुसार किसी एक विषय की प्रधानता से ही उसका वैसा नाम पड़ा है यह विज्ञजन भली प्रकार जान सकते हैं। जिन पुराणों में उक्त क्रम को रूपान्तर में प्रकट किया है वहां जिज्ञासाओं के क्रम को भी उसी रूप में स्थिर किया गया है ऐसा समझना चाहिये। देवी भागवत में जिज्ञासानिवृत्ति की दृष्टि को एक तरफ रखकर केवल आक्षरिक समता के अनुसार ही गणना की है यथा मत्स्य, मार्कण्डेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्माण्ड, वामन, वाराह विष्णु, वायु इत्यादि। संस्कृत साहित्य का नियम है कि- लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धि: अर्थात्- लक्षण और प्रमाणों से ही किसी विषय की सिद्धि होती है, नाम मात्र के ही निर्देश से नहीं। अत: पीछे जिन अष्टादश पुराणों के नाम संख्या और क्रम का विवेचन किया गया है अब उनके लक्षणों और प्रमाणों का सम्बन्ध पूर्वक निर्देश किया जाता है।

1- ब्रह्म पुराण- (क) पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मरीचि के प्रति जो कथन किया था वह ब्रह्म-पुराण है, इसकी श्लोक संख्या तेरह हजार है। (ख) ब्रह्मपुराण का प्रमाण (अयुत) दस हजार है। उपर्युक्त दोनों प्रमाणों में श्लोक संख्या विभिन्न लिखी गई है, उपलब्ध ब्रह्मपुराण में दश हजार सात सौ पद्य मिलते हैं, इस द्विविध विरोध का परिहार यह है कि- वैदिक काल से गुरु शिष्य सम्प्रदाय द्वारा उक्त पुराण के 13 हजार पद्य चले आ रहे थे, परन्तु जब वेदव्यास जी ने ब्रह्मपुराण का संकलन किया तो तात्पर्य्य प्राधान्य से वही प्रसङ्ग 13 हजार के बजाय **(क्रमश:)**

रवींद्रनाथ टैगोर

ललित गर्ग

7 अगस्त नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। वे एक बंगाली कवि, उपन्यासकार, संगीतकार, चित्रकार और नाटककार थे, जिन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत को महत्वपूर्ण रूप से बदला। एक्यूट यूरेमिया और यूरिनरी ब्लैडर में रुकावट के कारण 80 वर्ष की आयु में 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हो गया।

साहित्य, संगीत, रंगमंच और चित्रकला सहित विभिन्न कलाओं में महारत रखने वाले गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर मूलत: प्रकृति प्रेमी थे और वह देश विदेश चाहे जहां कहीं रहें, वर्षा के आगमन पर हमेशा शांतिनिकेतन में रहना पसंद करते थे। रवीन्द्रनाथ अपने जीवन के उत्तरार्ध में लंदन और यूरोप की यात्रा पर गए थे। इसी

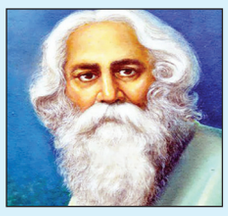

दौरान वर्षाकाल आने पर उनका मन शांतिनिकेतन के माहौल के लिए तरसने लगा। उन्होंने अपने एक नजदीकी से कहा था कि वह शांतिनिकेतन में रहकर ही पहली बारिश का स्वागत करना पसंद करते हैं। गुरुदेव ने गीतांजलि सहित अपनी प्रमुख काव्य रचनाओं में प्रकृति का मोहक और जीवंत चित्रण किया।

समीक्षकों के अनुसार टैगोर ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के जरिए शहरी मध्यम वर्ग के मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से वर्णन किया है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बांग्ला विभाग में रीडर बताया कि बांग्ला में बंकिम चंद्र और शरद चंद्र का कथा साहित्य काफी लोकप्रिय हुआ। लेकिन इनकी कथाओं में पात्र प्राय: ग्रामीण जीवन से जुड़े होते थे। रविन्द्रनाथ के कथा साहित्य में शहरी मध्यम वर्ग का एक नया संसार पाठकों के समक्ष आया।

रवीन्द्रनाथ टैगोर के गोरा, चोखेर बाली, घरे बाहिरे जैसे कथानकों में शहरी मध्यम वर्ग के पात्र अपनी तमाम समस्याओं और मुद्दों के साथ प्रभावी रूप से सामने आते हैं। इन रचनाओं को सभी भारतीय भाषाओं के पाठकों ने काफी पसंद किया क्योंकि वे उनके पात्रों में अपने जीवन की छवियां देखते हैं। टैगोर का जन्म सात मई 1861 को बंगाल के एक सभ्रांत परिवार में हुआ। बचपन में उन्हें स्कूली शिक्षा नहीं मिली और बचपन से ही उनके अंदर कविता की कोपलें फूटने लगीं। उन्होंने पहली कविता सिर्फ आठ साल की उम्र में लिखी थी और केवल 16 साल की उम्र में उनकी पहली लघुकथा प्रकाशित हुई। साहित्य की शायद ही कोई विधा हो जिनमें उनकी रचनाएं नहीं हों। उन्होंने कविता, गीत, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं में रचना की। उनकी कई कृतियों का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है। अंग्रेजी अनुवाद के बाद पूरा विश्व उनकी प्रतिभा से परिचित हुआ। रवींद्रनाथ के नाटक भी अनोखे हैं। वे नाटक सांकेतिक हैं। उनके नाटकों में डाकघर, राजा, विसर्जन आदि शामिल हैं।

रवीन्द्रनाथ की प्रसिद्ध काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बांग्ला के इस महाकवि ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार के निर्दोष लोगों को गोलियां चलाकर मारने की घटना के विरोध में अपना नोबेल पुरस्कार लौटा दिया था।

इसराईल के लिए युद्ध विराम हार के समान होगा

सईद नकवी

टारनटिनो की फिल्म 'जैंगो अनचेन्ड' का क्रूर यथार्थवाद शायद पेट के कमजोर लोगों को भी उल्टी करवा दे। अमरीका के सुदूर दक्षिण में रहने वाला एक श्वेत बागान मालिक अपने लिविंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ 2 मजबूत गुलामों को लड़ते हुए देखता है, दोनों कम से कम तब तक लड़ते हैं जब तक कि उनमें से एक दूसरे की आंखें नहीं निकाल लेता। बाहर, भेडियों से भी बड़े आकार के भूखे कुत्तों का एक झुंड एक गुलाम पर छोड़ दिया जाता है जो पेड़ पर चढने की व्यर्थ कोशिश करता है।

लीयर जंगल में विलाप करते हुए कहता है, ''जैसे आवारा लड़कों के लिए मक्खियां हैं, वैसे ही हम भगवान के लिए भी हैं वे हमें अपने मनोरंजन के लिए मारते हैं।'' बेंजामिन नेतन्याहू ने कैपिटल हिल में अमरीकी कांग्रेसियों से जो कुछ भी निकलवाया, उनके सामने सभी खड़े होकर तालियां बजाने वाले फीके पड़ गए। वे अपनी सीटों पर कीलों की तरह खड़े होने से नहीं रुक रहे थे। यह पहली बार नहीं है जब नेतन्याहू ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को अपने पक्ष में किया हो। कांग्रेस ने 4 मौकों पर नेतन्याहू की कोरियोग्राफी के आगे घुटने टेक दिए हैं। इस तरह उन्होंने कांग्रेस के सामने सबसे अधिक बार उपस्थित होने के मामले में विंस्टन चर्चिल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

एक बार राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वाशिंगटन में उनकी उपस्थिति का विरोध किया था। नेतन्याहू ने व्हाइट हाऊस की अवहेलना की और संयुक्त सत्र को

संबोधित किया, लोगों ने एक के बाद एक खड़े होकर तालियां बजाईं। इसराईल का असाधारण प्रभाव वाशिंगटन को क्या समझाता है? मैंने प्रधानमंत्री, यित्जाक शमीर, यित्जाक राबिन, शिमोन पेरेज और नेतन्याहू का साक्षात्कार लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेतन्याहू अपने अमरीका को बाकी सभी से बेहतर जानते हैं। इसके पीछे सरल कारण हैं। हार्वर्ड और एम.आई.टी. में अध्ययन करने के कारण उन्हें एक व्यापक, प्रभावशाली नैटवर्क मिला, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत से विकसित किया है।

1984 से 88 तक संयुक्त राष्ट्र में इसराईल के राजदूत के रूप में उनके कार्यकाल ने उन्हें न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में यहूदियों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने और मजबूत करने में मदद की। तेल अवीव के बाद, न्यूयॉर्क में यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी है और यह दुनिया का सबसे प्रभावशाली शहर है। विश्लेषकों ने यू.एस. में इसराईल लॉबी को एक ऐसी संस्था के रूप में उद्धृत किया है जो अमरीकी विदेश नीति को इसराईल के हितों के साथ जोड़ती है।

वास्तव में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफैसर जॉन मियर्सचाइमर और हार्वर्ड के प्रोफैसर स्टीफन वॉल्ट द्वारा इस विषय पर एक मौलिक कार्य 'इसराईल लॉबी और अमरीकी विदेश नीति' बताता है कि अमेरिकी प्रतिष्ठान की सभी शाखाओं में लॉबी के जाल कितने गहरे हैं। सैन्य सटीकता और असामान्य चापलूसी के मिश्रण के साथ जंपिंग जैक अभ्यास करने वाले अमरीकी लोगों के प्रतिनिधियों का वर्णन करने के लिए शर्मनाक एक हल्का शब्द है। क्या इसराईल से संबंधित मामलों में अमेरिकी लोकतंत्र में लोगों का कोई महत्व नहीं है? क्या यह केवल पूंजीदाताओं और लॉबी का एक सर्कस है। नैशनल राइफल एसोसिएशन किसी भी सुधार को सफलतापूर्वक विफल कर देगा, भले ही बंदूक हिंसा से हर दिन स्वतंत्र भूमि पर 12 स्कूली बच्चे मारे जाते हों।

1948 की नकबा या तबाही भयानक थी जब इसराईल के गांवों को फिलिस्तीनियों से खाली कर दिया गया था। आगे भी इसी तरह की भयावहताएं हुई हैं लेकिन वर्तमान क्रूरताओं की अंतहीनता फिलिस्तीनियों के लिए बेहतर भविष्य का अग्रदूत है। सभी पिछले विनाश इसराईल के आत्मविश्वास का परिणाम थे। इसराईल जानता था कि उसके सभी नखरे नजरअंदाज कर दिए जाएंगे और कभी-कभी एकमात्र महाशक्ति द्वारा प्रोत्साहित भी कि ए जाएंगे। रक्षा सचिव कैस्पर वेनबर्गर की इसराईल को मध्य पूर्व में अमेरिका के न डूबने वाले विमानवाहक के रूप में परिभाषित करना उचित था, केवल तब तक जब तक अमरीका एक निर्विवाद महाशक्ति था।

2008 में लेहमैन ब्रदर्स के टाइटैनिक की तरह डूबने के बाद, आधिपत्य के पतन को रोका नहीं जा सका। उदाहरण के लिए मिल्ट्री इंडस्ट्रियल काम्प्लैक्स (एम.आई.सी) जैसे कई अमरीकी संस्थानों ने अपनी चमक खो दी है । इस बहुचर्चित एम.आई.सी ने अमरीका को वियतनाम, इराक जीतने में सक्षम नहीं बनाया है और हम अगस्त 2021 में 20 साल के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से गंदी वापसी को स्पष्ट रूप से याद करते हैं। एम.आई.सी. देशों को नष्ट करने में मदद कर सकता है, युद्ध जीतने में नहीं।

पुतिन को यूक्रेनी रंगमंच में उकसाने का एक उद्देश्य अमरीका को खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाना था। इसके विपरीत हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से जो बाइडेन को बाहर होना पड़ा। पुतिन, शी जिनपिंग के भरोसेमंद हाथों को थामे हुए, एक वैश्विक राजनेता के रूप में प्रशंसनीय लग रहे हैं, दोनों जी-7 से आगे ब्रिक्स का रास्ता तय कर रहे हैं। इस बीच नेतन्याहू ने खुद को एक कोने में रख लिया है। वह बाघ से नहीं उतर सकता क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो बाघ उसे खा जाएगा। इसलिए उसे लडना जारी रखना चाहिए और फिलिस्तीनियों पर बमबारी जारी रखनी चाहिए। उन्हें एक और कारण से भी लडना जारी रखना होगा क्योंकि उन्होंने हमास पर पूर्ण विजय का वायदा किया है, जो सभी गणनाओं के अनुसार एक असंभव प्रस्ताव है।

लोग भूल जाते हैं कि सऊदी अरब के साथ अमरीका के संबंध 1948 में इसराईल के निर्माण से पहले के हैं। 1945 में राष्ट्रपति रूजवैल्ट और सऊदी राजशाही के संस्थापक शाह सऊद ने शीत युद्ध के संदर्भ में सुरक्षा की गारंटी के बदले में अरब तेल को पश्चिम द्वारा कैसे सांझा किया जाएगा। इस पर समझौतों की पुष्टि करने के लिए स्वेज नहर में यू.एस.एस. क्विंसी पर मुलाकात की थी।

जब 1990-91 में शीत युद्ध समाप्त हुआ, तो सुरक्षा नीतियों के लिए तेल को बनाए रखने के लिए अरबों को डराने के लिए ईरानी क्रांति, शिया धुरी, इस्लामी आतंक को लाया गया। इसलिए चीन के दबाव में आकर सऊदी अरब ने तेहरान से हाथ मिलाया है। यह वास्तव में वैश्विक दक्षिण में शामिल हो गया है। यह इसराईल नहीं कर सकता। चीन के इशारे पर, हमास और फतह सहित सभी फिलिस्तीनी समूह युद्ध के अगले दिन गाजा के प्रबंधन के लिए हाथ मिलाने पर सहमत हो गए हैं।

आज का इतिहास

1789 संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध विभाग की स्थापना की।
1814 रूस में उनके अस्तित्व को मंजूरी मिलने के बाद पोप पियस VII ने दुनिया भर में सोसाइटी ऑफ इसाइज (जेसुइट्स) की स्थापना करने के लिए बुलियन सॉलिटेक्डो सर्वव्यापार का आदेश दिया।
1888 फिलाडेल्फिया थियोफ़िलस ने घूमने वाला वैन दरवाजा बनाया।
1909 न्यूयॉर्क शहर छोड़ने के नौ दिन बाद, तीन दोस्तों के साथ, एलिस हुइलेरमासी, सैन फ्रांसिस्को में यू.एस. में एक वाहन चलाने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए पहुंचे।
1933 इराकी सैनिकों द्वारा दाहुक और मोसुल जिलों में शिमले नरसंहार को अंजाम देते हुए अनुमानित 3,000 असीरियों का कत्ल कर दिया गया था।
1935 फ्लाइंग चींटियों को लंदन, इंग्लैंड, यहां तक कि एक टेनिस टूर्नामेंट बाधित कर रहे थे। हानिकारक कीड़ों की एक बड़ी मात्रा पेंट्रीज़ पर आक्रमण कर रही थी और हर दरवाजे पर इकट्ठा हो रही थी। अधिकारियों का कहना है कि यह 25 वर्षों में महामारी का सबसे विनाशकारी हमला था।
1936 अल्मेंद्रेलोजो की लड़ाई और सिगुएंजा की लड़ाई शुरू हुई।
1941 सोवियत नौसेना के जुड़वां इंजन बमवर्षक ने बर्लिन पर हमला किया।
1942 द्वितीय विश्व युद्ध-यू.एस. मरीन ने सोलोमन द्वीप में गुआडलकैनाल और तुलागी पर लैंडिंग के साथ ग्वाडलकाल अभियान का पहला अमेरिकी शुरू किया।
1943 स्मोलेंस्क की दूसरी लड़ाई पूर्वी मोर्चा पर शुरू हुई।
1944 आईबीएम ने पहले प्रोग्राम-नियंत्रित कैलकुलेटर हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी को प्रस्तुत किया, जिसके बाद इसे मार्क। (चित्र) के रूप में जाना जाने लगा।
1944 51 फीट लंबाई, 8 फीट ऊंचाई और पांच टन के वजन वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण हुआ।
1946 ब्रिटेन ने पहली बार सिक्के पर एक अश्वेत की तस्वीर उकेरने को मंजूरी दी।
1959 एक्सप्लोरर 6 को मानव रहित अमेरिकी अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी की पहली उपग्रह तस्वीरों को पकड़ने के लिए कक्षा में भेजा गया था। बाद में सितंबर में, नासा ने फ़ोटोग्राफ़ को विश्व प्रेस को जारी किया। यह मेक्सिको था जिसने 6 पर कब्जा कर लिया था।
1959 एक्सप्लोरर 6 ने पहली बार अंतरिक्ष से धरती की ली गई तस्वीर प्रसारित की।

राजनाथ सरकार के ऐसे ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी रोक

अजय कुमार

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बैंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण प्रक्रिया मे बड़ा बदलाव करते हुए अनुसूचित जातियों में अति पिछड़ी अनुसूचति जातियों को चिन्हित करके उन्हें फायदा पहुंचाने के लिये कोटा में कोटा का जो आदेश पारित किया है। वह हिन्दुस्तान में लम्बे समय से चल रही आरक्षण की सियासत में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अभी इस पर बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के बड़े नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, फिलहाल सिर्फ बीजेपी ही अनुसूचित जातियों को कोटे में कोटा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गद्गद है और उसके शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान द्वारा इसे सत्य की जीत बताया गया है। सबसे खास बात यह है कि पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण में जैसे क्रिमी लेयर को बाहर रखा जाता था, वैसे ही अब एससी/एसटी को मिलने वाले आरक्षण में भी क्रिमी लेयर लागू होगी।

बहरहाल, यूपी में ऐसा ही प्रयास 23 साल पूर्व 2001 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया था, जिस पर राजनाथ सिंह सरकार में ही राज्य मंत्री और शिकोहाबाद से विधायक अशोक यादव अपनी ही सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गये थे और तब सुप्रीम कोर्ट ने उनके (राजनाथ सरकार) फैसले पर रोक लगा दी थी जिसे अब उसने कानून बना दिया है। अब राजनाथ सिंह मौजूदा केंद्र सरकार में गृहमंत्री हैं। राजनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के समूहों को उप समूहों बांटकर तय आरक्षित कोटे में विभाजन का प्रयास किया था। राजनाथ सरकार ने जो समूह बनाए थे वे आय आधारित क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर जैसे नहीं थे, बल्कि कई जातियों को आरक्षण के दायरे से ही बाहर करने का प्रयास किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजनाथ सरकार की कोशिशों पर पानी फेर दिया था, और उनके प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया।

उस समय उत्तर प्रदेश की राजनाथ सिंह सरकार ने पिछड़ी जातियों के 27 फीसदी कोटे में यादव, अहिर और यदुवंशियों का कोटा 5 फीसदी तय किया था, जबकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के 21 फीसदी कोटे में जाटव, चमार और धुसिया जातियों का कोटा 10 फीसदी तय किया गया था। अनुसूचित जनजातियों का कोटा घटा कर दो से एक फीसदी कर दिया गया था, ताकि प्रदेश में कुल कोटा 50 फीसदी तक ही बना रहे। राजनाथ सरकार के फैसले का राजनीतिक दलों समेत जाति समूहों ने भी कड़ा विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द कर चुका है, हालांकि राजनाथ सिंह की निजी वेबसाइट पर ये एक उपलब्धि के रूप में दर्ज है। बता दें जून, 2001 में राजनाथ सिंह एक समिति बनाई थी, जिसे उन्होंने 'सामाजिक न्याय समिति' नाम दिया था। यूपी सरकार के तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, स्वास्थ्य मंत्री रमापति शास्त्री और विधान परिषद सदस्य दयाराम पाल सदस्य थे। समिति को ये पता करने जिम्मेदारी दी गई थी कि आरक्षण का लाभ उन्हें मिल पा रहा है या नहीं, जिन्हें इनकी आवश्यकता है। समिति को आरक्षण नीति में बदलाव की सिफारिशें देने का निर्देश भी दिया गया था। भाजपा सरकार ने ये फैसला 'आरक्षण नीतियों की गड़बड़ियां' दूर करने के

लिए किया था।

सामाजिक न्याय समिति ने 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। भाजपा सरकार ने उसके बाद एक सामाजिक न्याय (30 जुलाई से 6 अगस्त, 2001) सप्ताह मनाया, जिसमें समिति के सुझावों पर राय मांगी गई थी। राजनाथ सरकार ने उस समय सरकार नौकरियों में जातियों के कुल प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण भी कराया था। उस सर्वे के बाद राजनाथ सरकार ने ये नतीजा निकाला था कि आरक्षण अधिकांश लाभ पिछड़ी जातियों में यादवों को और अनुसूचित जातियों में जाटव, चमार और धुसिया को ही मिल रहा है। इन्हीं नतीजों के बाद यादवों और जाटवों को आरक्षण सी?मित कर दिया गया था।

दरअसल, हाल में आरक्षण में कोटे में कोटा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस समय आया जब सात जजों की संविधान पीठ ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में 2004 के उसके फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है या नहीं, पर विचार कर रह थी, जिसमें माना गया था कि अनुसूचित जातियों के बीच किसी तरह का उप-विभाजन नहीं हो सकता। ताजा फैसला उन राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा जो प्रमुख अनुसूचित जातियों की तुलना में आरक्षण के बावजूद को आरक्षण का व्यापक लाभ देना चाहते हैं। कोर्ट के इस तथ्य पर मुहर लगाने के बाद कि ऐतिहासिक और अनुभवजन्य साक्ष्य यही बताते हैं कि अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग नहीं हो सकतीं, राज्यों को आरक्षण पर अपने हिसाब से कानून बनाने का मौका मिल सकेगा। उप-वर्गीकरण रणनीति का पंजाब में वाल्मीकि और महजबी सिखों, आंध्र प्रदेश में मडिगा के अलावा बिहार में पासवान, यूपी में जाटव और तमिलनाडु में अरूंधतिर समुदाय पर सीधा असर पडेगा। इस मामले में शीर्ष कोर्ट की पीठ ने 8 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। उस समय अदालत ने कहा कि उप-वर्गीकरण की अनुमति न देने से ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, जिसमें इस वर्ग के सम्पन्न लोग ही सारे लाभ हड़प लेंगे।

बता दें इससे पहले, 2004 में पांच न्यायाधीशें की पीठ ने फैसला दिया था कि यह अधिसूचित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत किस समुदाय को आरक्षण का लाभ मिल सकता है। राज्यों को इसमें किसी भी तरह के संशोधन का अधिकार नहीं है। तब पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से वर्ष 2000 में लाए गए इसी तरह के एक कानून को रद्द कर दिया। ई.वी. चिन्नैया मामले में शीर्ष कोर्ट ने आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम, 2000 को समानता के अधिकार का उल्लंघन करार देते हुए रद्द कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह.एक के बहुमत से एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधान सम्मत बताया वहीं चार न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जताई जैसी ओबीसी आरक्षण में है सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह.एक के बहुमत से एससी.एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधानसम्मत बतायाए वहीं चार न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू बात अभी आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कि जाये तो सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह-एक के बहुमत से एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधान सम्मत बताया, वहीं चार न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जताई, जैसी ओबीसी आरक्षण में है। सच यह है कि ओबीसी समाज की तरह एससी-एसटी समुदाय में भी कई जातियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति न केवल कहीं कमजोर है, बल्कि उन्हें अपने ही वर्ग की अन्य जातियों से भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी सच्चाई है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यह भी एक तथ्य है कि एससी-एसटी समुदाय में कई जातियां ऐसी हैं, जिन्हें आरक्षण का न के बराबर लाभ मिला है। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियां उठाती हैं। यही स्थिति ओबीसी में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है।

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी दे दिया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार का दुरुपयोग होने की भी आशंका जताई है, क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल वोट बैंक बनाने के लालच में एससी-एसटी जातियों का मनमाना उपवर्गीकरण कर सकते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि राजनीतिक दलों यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया है, न कि वोट बैंक की राजनीति का हथियार। एससी-एसटी समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण में बंटवारा किया जाना इसलिए समय की मांग है, क्योंकि आइएएस-आइपीएस अधिकारियों के बच्चों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी स्थिति गांव में रहने वाले भूमिहीन-निर्धन लोगों के बच्चों जैसी है। अच्छा होगा कि एससी-एसटी आरक्षण का उप -वर्गीकरण करने के साथ ही उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाए। आरक्षित वर्गों में जो भी अपेक्षाकृत सक्षम और संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना सामाजिक न्याय की मूल भावना के खिलाफ तो है ही, वंचित-निर्धन लोगों के साथ किया जाने वाला अन्याय भी है। आरक्षण प्रदान करते समय यह देखा ही जाना चाहिए कि उसका लाभ पाने वाला पात्र है या नहीं?

पुतिन-बाइडन की ताजा पहल का क्या है अर्थ

अमिताभ सिंह

शीत युद्ध के खत्म होने के बाद रूस और पश्चिमी देशों के बीच कैदियों की अब तक की सबसे बड़ी अदला-बदली हुई। कुल 26 कैदी रिहा किए गए, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। तुर्किये की मदद से अमेरिका और रूस इस अदला-बदली के लिए समझौते तक पहुंचे। यह कदम कई मायनों में अनोखा रहा। इसने शीत युद्ध की याद ताजा करा दी, जहां पूरी दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हो रही घटनाओं की बंधक थी। यह वर्तमान समय में दो प्रमुख शक्तियों (और शायद चीन) के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा को भी दर्शाता है। एक-दूसरे के यहां बंद कैदियों को बंधक की तरह देखा जाता है। कई बार इस तरह की रिहाई कानून के खिलाफ होती है। कैदी कई बार हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए जेल में बंद होते हैं। लेकिन, इस तरह के समझौते के चलते सरकारों को उन्हें छोड़ना पड़ता है। शीत युद्ध के दौरान, कैदियों का आदान-प्रदान आमतौर पर विभाजित बर्लिन के ग्लेनिके ब्रिज पर किया जाता था। इसे जासूसों का पुल भी कहते थे। कैदियों की मौजूदा अदला-बदली 50 और 60 के दशक की याद दिलाती है, जब शीत युद्ध की प्रकृति अनिश्चित और शायद खतरनाक थी। उस समय खेल के नियम परिभाषित नहीं थे। 70 और 80 के दशक में जाकर शीत युद्ध संस्थागत हुआ। हम 50 और 60 के दशक का दोहराव देख रहे हैं। इस कोल्ड वॉर 2.0 के दोनों ही पक्षों के सामने अनिश्चित स्थिति है। दोनों एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और जानते हैं कि अगर स्थिति बिगड़ी, तो नतीजा अनिश्चित होगा। यह डील दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के लिए उनके कार्यकाल की यह एक प्रमुख उपलब्धि हो सकती है। इसी तरह, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश में यह साबित करने में मदद मिलेगी कि उनके नेतृत्व में सब ठीक है। जिन कैदियों की रिहाई हुई, उनमें दो नाम ऐसे हैं, जो रूस और जर्मनी के लिए बहुत मायने रखते हैं। इनमें एक हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गर्शकोविच और दूसरे हैं वादिम क्रासिकोव। इवान को रूस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं, वादिम पर आरोप है कि उन्होंने मॉस्को मेट्रो बम धमाकों के आरोपी जेलिमखान खानगोशविली की हत्या की। गिरफ्तारी के डर से जेलिमखान भागकर जर्मनी चला गया था। उसकी हत्या करके क्रासिकोव रूस में नैशनल हीरो बन गए। पहले प्लान था कि क्रासिकोव को इस साल जनवरी में एलेक्सी नवलनी के बदले रिहा किया जाएगा। नवलनी, पुतिन और उनकी नीतियों के कट्टर आलोचक थे। वह रूस की आर्कटिक पीनल कॉलोनी में रहस्यमय परिस्थितियों में मरे पाए गए और इसकी वजह से कैदियों की अदला-बदली में देरी हुई। पुतिन ने टकर कार्लसन के साथ अपने इंटरव्यू में क्रासिकोव की रिहाई पर भी चर्चा की थी। मौजूदा संघर्ष के बीच तुर्किये ने महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाई और दोनों पक्षों के बीच पुल का काम किया है। रूस-यूक्रेन संघर्ष में भी तुर्किये की ऐसी ही भूमिका देखने को मिली थी। तब उसने अफ्रीका में खाद्य संकट को हल करने और बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए यूक्रेन से अनाज भेजने में मदद की थी। इसका असर यूरोप और कई विकसित देशों पर भी पड़ रहा था। तुर्किये नैटो का सदस्य है। काला सागर के रास्ते होने वाले व्यापार में वह एक ट्रांजिट पॉइंट है। इसके अलावा पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच एक भू-रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। इस पूरी कवायद में तुर्किये की स्थिति उसकी भूमिका को बहुत बढ़ा देती है।

नेतृत्व के लिए भाजपा करे आत्ममंथन

आदिति फडणीस

दिल्ली में तीन युवाओं की हुई मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। ये तीनों युवा ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी में डूब गए क्योंकि उस इलाके में जल-निकासी व्यवस्था नहीं थी या पर्याप्त तरीके से काम नहीं कर रही थी। करीब एक साल पहले, दिल्ली विश्वविद्यालय के पास के इलाके मुखर्जी नगर में एक ऐसे ही संस्थान का वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

उस वक्त वहां आग लगी थी और बच्चों को इमारत की ऊपरी मंजिल से कूदते और मौत को गले लगाते देखा गया क्योंकि इमारत पूरी तरह से आग की लपेट में आ चुकी थी और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हवा के संचार के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होने से कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस बन गई जिसके कारण भी कई मौतें हुई हैं। उसी इलाके में अवैध निर्माण की वजह से घरों की नींव कमजोर पड़ने से कई मकान गिरने की घटनाएं भी हुई हैं। ये सभी घटनाक्रम दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत, भ्रष्टाचार या लापरवाही की ओर इशारा करते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ऐसा फिर से हो सकता है। आम आदमी पार्टी (आप) एमसीडी को नियंत्रित करती है। यह तथ्य है कि आप और एमसीडी के अधिकारियों, खासतौर पर अफसरशाहों की एक-दूसरे से नहीं बनती है। वर्ष 2018 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी और तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर आप के समर्थकों द्वारा किए गए हमले को लेकर अदालती लड़ाई चली जिसमें प्रकाश को आंशिक जीत मिली थी।

अफसरशाहों का एक वर्ग जो आप से सहमत नहीं होता है उसे दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय में अपील करने का एक तैयार मंच मिल जाता है। इससे आप के इस तर्क को बल मिल जाता है कि जो उनके साथ नहीं हैं वे उसके

खिलाफ हैं। वैसे भी बेहतर शासन के लिए सत्ता के दो केंद्र ठीक नहीं होते हैं। वर्ष 2022 में, आप ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से एमसीडी का नियंत्रण छीन लिया और इस तरह एमसीडी में भाजपा का 15 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। आप को 134 वार्ड मिले लेकिन भाजपा 104 वार्ड के साथ काफी पीछे भी नहीं थी। इसके अलावा वोट के मामले में सिर्फ तीन प्रतिशत का अंतर था। यह सब तब हुआ जब भाजपा ने दिल्ली की स्थानीय शासन योजना का प्रयोग करते हुए बदलाव किया।

वर्ष 2012 में शीला दीक्षित ने भाजपा को कमजोर करने की उम्मीद में स्थानीय सरकार को तीन हिस्सों में बांट दिया था, हालांकि इसकी भी अपनी समस्याएं थीं और ये सब 2017 में सामने आने लगीं जब भाजपा ने एमसीडी चुनावों में 270 में से 181 वार्ड जीतकर भारी जीत दर्ज की। आप वर्ष 2015 से ही दिल्ली विधानसभा में भारी जीत के साथ सत्ता में बनी थी लेकिन 2017 के चुनावों ने ये साबित कर दिया कि इसकी जड़ें भी कमजोर हैं और यह केवल 49 वार्ड ही जीत सकी। हालांकि 2022 के चुनावों के बाद सब ठीक हुआ। वर्ष 2022 के चुनावों से ठीक पहले भाजपा ने तीन जोन को एक इकाई में मिला दिया लेकिन इसे फिर से चुनाव में आप के सामने हार का मुंह देखना पड़ा।

यह सब क्यों महत्त्वपूर्ण है? भ्रष्टाचार, लापरवाही और शहरी प्रशासन से जुड़ी समस्याओं के अलावा एमसीडी की कार्यप्रणाली में राजनीति केंद्र में है। पिछले वर्ष एमसीडी में चुनाव की स्थायी समिति को लेकर मारपीट की नौबत आ गई। आप और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच पानी की बोतलें फेंकने के साथ ही गुत्थम-गुत्थी तक शुरू हो गई। इसके अलावा मेयर का चुनाव भी समान रूप से विवादास्पद रहा। आप यह पूछ सकते हैं जब वे हर वक्त लड़ते रहते हैं तब इन पार्षदों को काम करने का वक्त कब मिलता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी यही सवाल पूछा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी दबाव बनाते हुए आरोप लगाया है कि जब दिल्ली सरकार को नालियों की सफाई कराने के लिए कहा गया तब इसने उस प्रस्ताव पर कोई कदम क्यों नहीं उठाए। वहीं आप का कहना है कि जब दिल्ली सरकार काम करना चाहती हैं तब उपराज्यपाल कार्यालय काम नहीं देते। आप यह सोच रहे होंगे कि इन बातों के मद्देनजर दिल्ली में भाजपा के उभार की पूरी गुंजाइश बन सकती है जिस पार्टी में कभी मदन लाल खुराना जैसे दिग्गज नेता थे और उन्होंने कभी दिल्ली का नेतृत्व किया था। पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, वीरेंद्र सचदेवा ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कराए और आप के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया।

लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में भीड़ सीमित ही रही। पार्टी से इतर सामान्य मतदाताओं तक पहुंच बनाने में पार्टी सफल नहीं रही है जो रोष में हैं। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो अरविंद केजरीवाल के कद का हो। सुधांशु त्रिवेदी या बांसुरी स्वराज पार्टी में नया जोश भर सकते हैं जिसकी राजधानी दिल्ली में जरूरत है। भारत में कोई भी शहर इतना नहीं बदल रहा है जितनी दिल्ली बदल रही है। दूसरे राज्यों से आए लोग इसका मजबूत आधार हैं। लेकिन10 साल पहले जिस उम्र, क्षेत्र और पृष्ठभूमि के लोग यहां आ रहे थे, उसमें अब बहुत अंतर है। दिल्ली की नई राजनीति-अर्थव्यवस्था दरअसल आप के उभार का नतीजा रही। भाजपा को खुद को इस यथार्थ के अनुरूप खुद को ढालना होगा।

अमेरिका की चुनावी जटिलताएं

देवांशु दत्ता

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रुचि की बात करें तो पियरे ट्रूडो का कथन एकदम सटीक लगता है, 'अमेरिका के साथ रहना हाथी के साथ सोने के समान है। वह चाहे जितना दोस्ताना और शांत स्वभाव का हो लेकिन उसकी हर हरकत और घुरघुराहट का असर आप पर होता है।' चौंतीस करोड़ की आबादी वाला अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2023 में 28 लाख करोड़ डॉलर आकार के साथ उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी थी। अमेरिकी सेना ने 2023 में 916 अरब डॉलर यानी अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.5 फीसदी रक्षा क्षेत्र पर व्यय किया। यह राशि दुनिया भर में रक्षा पर होने वाले कुल खर्च की 40 फीसदी है। दुनिया की आरक्षित मुद्रा वही छापता है और अधिकतर देशों का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार भी वही है।

अमेरिका की चुनावी व्यवस्था जटिल है। उसके सभी 50 राज्यों में दो सीनेटर होते हैं और उपराष्ट्रपति (सीनेट का 101वां सदस्य) के पास 100 सदस्यीय सीनेट में निर्णायक मत होता है। सीनेटरों को जनता चुनती है। हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स निचला सदन होता है। इसमें 438 सदस्य होते हैं और राज्य की आबादी के हिसाब से ही उसे निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन किया जाता है। इस सदन के चुनाव जनता के मतों से होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता के मतों को निर्वाचक मतों (इलेक्टोरल वोट) में बदलकर होता है। इसमें जनता के मतों से चुने गए हरेक सीनेटर के पास एक और हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव के सदस्य के पास एक निर्वाचक मत होता है। इस प्रकार कुल 538 निर्वाचक मत होते हैं यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 270 निर्वाचक मतों की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक राज्य और वॉशिंगटन डीसी अपनी पसंद का राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करता है। जिस राज्य में जो भी टिकट जनता के ज्यादा मत पाता है, उस राज्य के सीनेटर और रिप्रजेंटेटिव के निर्वाचक मत उसी टिकट या

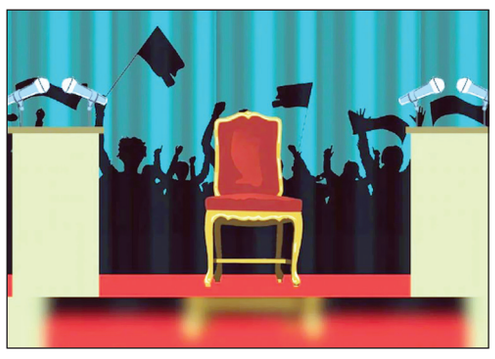

प्रत्याशी को मिल जाते हैं। अगर टेक्सस में जनता के ज्यादा मत रिपब्लिकन को मिलते हैं तो टेक्सस के दो सीनेटरों के निर्वाचक मत और वहां के 40 रिप्रजेंटेटिव के मत रिपब्लिकन उम्मीदवार को ही जाएंगे भले ही वे किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों।

अमेरिका में दो दलों वाली व्यवस्था है। डेमोक्रेटिक पार्टी को पिछले 10 राष्ट्रपति चुनावों में से सात बार जनता का बहुमत मिला है मगर पांच बार रिपब्लिकन सरकार रही है और पांच बार डेमोक्रेटिक सरकार। इसकी वजह यह है कि राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली में जनता के मत बहुत खराब तरीके से परिलक्षित होते हैं। सभी राज्यों में बराबर आबादी नहीं है मगर हर राज्य को दो सीनेटर मिलते हैं। यह वहां का संवैधानिक प्रावधान है जो देश की संघीय प्रकृति बरकरार रखने के लिए बना है। आखिरकार उसका नाम 'संयुक्त राज्य' है। हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव का आवंटन जनता के मतों और निर्वाचक मतों के बीच के अंतर को और अधिक बढ़ा देता है। अलास्का की आबादी सात लाख है और वायोमिंग की आबादी 5.70 लाख। किंतु हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में दोनों की तीन-तीन सीट हैं। कैलिफोर्निया की आबादी 3.9 करोड़ है और उसकी 55 सीट हैं। 3.1 करोड़ की आबादी वाले टेक्सस की 40 सीटें और 1.9 करोड़ की आबादी वाले न्यूयॉर्क की 28 सीट हैं। प्यूर्टो रिको अमेरिकी राज्य नहीं बल्कि 'टेरिटरी' है और जहां 30 लाख से अधिक अमेरिकी नागरिक रहते हैं। लेकिन वहां एक भी सीनेटर या रिप्रजेंटेटिव नहीं है। अगर आप आबादी अनुपात के हिसाब से देखें तो प्यूर्टो रिको में हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव की 18 सीट तथा दो सीनेटर होने चाहिए। कैलिफोर्निया में 150 से अधिक रिप्रजेंटेटिव तथा टेक्सस में 125 रिप्रजेंटेटिव होने चाहिए। इस हिसाब से देखें तो अलास्का और वायोमिंग के नागरिकों के मतों को अधिक वजन मिला है।

इसके अलावा राज्य अपने हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव क्षेत्रों की सीमाएं तय करते हैं और दोनों दल अपनी राजनीतिक संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए अपने नियंत्रण वाले राज्यों में समीकरण बनाने का काम करते हैं। राज्यों में मतदान के पंजीयन और प्रक्रियाओं के लिए नियम भी अलग-अलग होते हैं। इसका असर भी मतदान पर पड़ सकता है। डेमोक्रेट्स प्राय: उन राज्यों में बड़े मार्जिन से जीतते हैं, जहां आबादी का घनत्व अधिक है। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया इसके उदाहरण हैं। इसलिए वे अक्सर जनता के ज्यादा मत हासिल करते हैं। रिपब्लिकन के जीतने की अधिक संभावना कम घनत्व वाले राज्यों मसलन अलास्का और वायोमिंग में होती है। यही वजह है कि उन्हें 2000 और 2016 में जनता के मत हारने के बाद भी राष्ट्रपति चुनाव जीतने में मदद मिली थी। 2024 में एक प्रत्याशी 78 वर्ष का है और उसके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। वह यौन हमले का दोषी पाया गया है। उसने सार्वजनिक तौर पर 30,000 से अधिक झूठ बोले हैं। उसका कारोबार छह बार दिवालिया हो चुका है। फरवरी 2024 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन द्वारा 154 विद्वानों के एक सर्वेक्षण में उसे अमेरिका का अब तक का सबसे बुरा राष्ट्रपति करार दिया गया था। एक अन्य दावेदार 59 वर्षीय महिला है जो श्वेत नहीं है, लेकिन वह बेदाग है। वह उस प्रशासन का हिस्सा रही है, जिसने लगभग चमत्कारिक ढंग से आर्थिक हालात बदल डाले।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने में केंद्र की कोताही

योगेंद्र योगी

विपक्षी दलों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार रोकने के लिए कानून बनाने में नाकाम रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को लेकर याचिका पर सुनवाई स्वीकार करना स्वीकार कर लिया है। देश की शीर्ष अदालत ने वर्ष 2018 में एक जनहित रिट याचिका पर आदेश दिया था कि चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों के अलावा उनके परिवार के लोगों की सम्पत्ति और आय के स्त्रोतों की जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार कायदे-कानून बनाए। करीब 6 साल बीतने के बावजूद केंद्र सरकार इस आदेश की पालना करने में विफल रही। इस पर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। आश्चर्य की बात यह है कि लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने विपक्षी दलों के नेताओं को भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर कटाक्ष किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गुट को भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा बताया था। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हु कहा था कि विपक्षी नेता नोटों के बंडलों के साथ रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। झारखंड और बंगाल में ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं। वे दिल्ली की जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि राजनीति में बदलाव के लिए आए लोगों ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। पीएम ने कहा था कि शराब घोटाला हो या नेशनल हेराल्ड घोटाला, भ्रष्टाचारियों से एक-एक पैसा वसूला जाएगा। यह मोदी की गारंटी है। जिसने भी लूट की है, उसे जनता का पैसा वापस करना होगा। हम इस पर कानूनी राय लेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी भ्रष्ट लोगों के धन का एक्स-रे करेंगे। जिन्होंने लूट की है, उन्हें जेल जाना होगा। इतना ही नहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना एनडीए सरकार का एक मिशन है, न कि चुनावी लाभ का मामला। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और काले धन पर और अधिक कार्रवाई करने का संकल्प लेते हुए कहा कि सरकार ने जांच एजेंसियों को भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी आजादी दे दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्रवाई में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पहले आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ सबूतों के साथ गंभीर आरोप लगाने और बाद में लोकसभा चुनाव लडने के लिए उसके साथ गठबंधन करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बिना किसी झिझक के यह कहना चाहता हूं और देशवासियों को भी बताना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्ट लोगों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी है। सरकार कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें (जांच एजेंसियों को) ईमानदारी के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी व्यक्ति कानून से बच नहीं पाएगा। यह मोदी की गारंटी है।

मानसून में रेनकोट नहीं का ऐसे रखें ध्यान

बारिश के मौसम में रेनकोट बड़े काम की चीज होती है। खासकर जब ऑफिस जाना हो या जब बच्चे स्कूल जाते हैं और तेज बारिश होने लगे तो रेनकोट का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन बारिश के मौसम में रेनकोट का इस्तेमाल करने के बाद उसका सही से ध्यान नहीं रख जाता है तो रेनकोट ख़राब भी हो जाता है या रेनकोट के ऊपर फफूंदी के दाग भी लग जाते हैं। ऐसे में हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप रेनकोट को हमेशा नया बनाकर रख सकते हैं।

ऐसे करें सफाई

रेनकोट की सफाई करना काफी आसान है, लेकिन ध्यान से साफ नहीं किया गया तो रेनकोट ख़राब भी हो सकता है। इसलिए उसकी सफाई कर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। रेनकोट को साफ करने के लिए आपको माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए एक लीटर पानी में माइल्ड डिटर्जेंट को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और रेनकोट को डालकर कुछ देर छोड़ दें। कुछ देर बाद सॉफ्ट हाथों से साफ कर लें और हवा के नीचे के रख दें।

ऐसे निकाले दाग

अगर रेनकोट पर मिट्टी या फिर फिर किसी अन्य चीज का दाग लग गया है तो आप उसे आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बार नॉर्मल पानी से साफ कर लें। अब दाग वाली जगह पर नींबू के रस को डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। कुछ देर बाद सॉफ्ट क्लीनिंग ब्रश से दाग को साफ कर लें। साफ करने के बाद हवा के नीचे रख दें।

तेज धूप में न रखें

जी हां, अगर इस्तेमाल करने के बाद रेनकोट को तेज धूप में रखते हैं तो रेनकोट कभी भी ख़राब हो सकता है। इसलिए रेनकोट का इस्तेमाल करने के बाद तेज धूप में नहीं बल्कि फंखा के नीचे रख दें। जब रेनकोट से पानी पूरी तरीके से निकल जाए तो फिर आप उसे फोल्ड करके रख सकते हैं।

पैक करके रखने से पहले रखें ये ध्यान

ऐसा नही कि इस्तेमाल किया और सीधा फोल्ड करके रेनकोट को अंदर रख दिया। इससे रेनकोट कभी भी ख़राब हो सकता है। ऐसे में एक से दो-दिन सूखने के बाद ही रेनकोट को पैक करके अंदर रखें। रेनकोट पैक करने वक्त आप एक पेपर में नेप्थलीन की गोली लपेट लीजिए और अंदर रख दें। इससे रेनकोट फ्रेश रहेगा।

मानसून के मौसम में घर के अंदर होती है घुटन

तो अपनाएं ये कमाल के वेंटिलेशन डिजाइन

वेंटिलेशन एक अहम प्रक्रिया है, क्योंकि यह बासी हवा को ताजी हवा से बदल देता है। खराब वेंटिलेशन की वजह से कार्बन जमा हो सकता है और इससे घर में बैक्टीरिया भी बढ़ सकते हैं।

मानसून का मौसम खुशियों और त्योहारों का मौसम होता है, लेकिन साथ ही यह घर में घुटन और उमस का भी मौसम होता है। बंद खिड़कियां और दरवाजे, बारिश का पानी, और हवा में नमी घर के अंदर एक भारीपन सा माहौल पैदा कर सकती है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान वेंटिलेशन डिजाइन अपनाकर आप अपने घर को हवादार और खुशनुमा बना सकते हैं।

वेंटिलेशन डिजाइन क्या है

वेंटिलेशन डिजाइन, घरों में ताजी हवा के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। इसमें कमरे से प्रदूषित हवा को बाहर निकालकर बाहर से ताजी हवा दी जाती है।

वेंटिलेशन डिजाइन के कई फायदे हैं

- ठंड के मौसम में हवा की गुणवत्ता बनाए रखना
- गर्म मौसम में तापमान को कंट्रोल करना
- नमी, धुआं, खाना पकाने की गंध, और इनडोर प्रदूषकों से छुटकारा पाना
- अटारी में गर्मी के स्तर को कंट्रोल करना
- क्रॉलस्पेस और बेसमेंट में नमी को कंट्रोल करना
- दीवारों से नमी को दूर रखना
- पानी के इस्तेमाल के कारण नमी के प्रभाव को कंट्रोल करना
- कंप्यूटिंग गैजेट से केमिकल के उत्सर्जन को कंट्रोल करना
- खाना पकाने के कारण दहन को कंट्रोल करना
- घर में गंध को कंट्रोल करना
- घर के अंदर अलग से कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना

घर में वेंटिलेशन के कई तरह के हो सकते हैं

नेचुरल वेंटिलेशन

खिड़कियों और दरवाजों के जरिए हवा का आना-जाना। यह वेंटिलेशन का सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए, जब भी संभव हो, खिड़कियां और दरवाजे खोलकर ताजी हवा को घर के अंदर आने दें। विपरीत दिशाओं में खिड़कियां और दरवाजे खोलकर हवा को घर से गुजरने का रास्ता दें। छत या दीवारों में रोशनदान सेट करें ताकि ऊपर की गर्म हवा बाहर निकल सके। बाथरूम और रसोई में एयर वेंट लगाएं, जहां नमी और गंध जमा होने की संभावना होती है। घर के अंदर कुछ छोटे पौधे लगाएं जो हवा को शुद्ध करने में मदद करते हैं।

मेकैनिकल वेंटिलेशन

इसमें बाहरी पंखे, अटारी पंखे और पूरे घर के पंखे शामिल हैं। नए और मौजूदा दोनों तरह के ऊर्जा-कुशल घरों में इनडोर एयर क्वालिटी बनाए रखने के लिए यांत्रिक वेंटिलेशन की जरूरत होती है। छत के पंखे और टेबल फैन का इस्तेमाल करके हवा को घुमाएं। इसमें हीट रिकवरी वेंटिलेशन या एनर्जी रिकवरी वेंटिलेशन शामिल हैं। वेंटिलेशन एक अहम प्रक्रिया है, क्योंकि यह बासी हवा को ताजी हवा से बदल देता है। खराब वेंटिलेशन की वजह से कार्बन जमा हो सकता है और इससे इमारत में बैक्टीरिया भी बढ़ सकते हैं। इसलिए, वेंटिलेशन सिस्टम चुनते समय आपके घर के लेआउट और जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है। आप इन तरीकों से अपने घर में वेंटिलेशन बढ़ा सकते हैं

- मौजूदा वेंटिलेशन सिस्टम का सही इस्तेमाल करें
- खिड़कियां या जालीदार दरवाजे खोलें
- रसोई में वेंटिलेशन पंखा लगाएं

अपने घर में वेंटिलेशन कैसे बढ़ाएं

घर और खुले स्थानों की ओर हवा लाने के लिए पेड़ लगाएं। पेड़ों को एक-दूसरे के बहुत पास न लगाएं, क्योंकि पत्ते हवा को अंदर नहीं आने देते। तेज हवाओं के दौरान नुकसान से बचने के लिए पेड़ों और घर के बीच दूरी बनाएं। पेड़ से घर की दूरी पेड़ की ऊंचाई से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपके घर में विंडो एयर कंडीशनर है, तो उसे चलाएं जिसमें बाहरी हवा का प्रवेश या वेंट हो। वेंट खुला रहने दें। अगर आपके HVAC सिस्टम में बाहरी हवा का प्रवेश है, तो उसे खोलें। अगर आपने छत का पंखा नहीं लगवाया है, तो खुली खिड़की के पास जितना हो सके, एक स्टैंडअलोन पंखा लगाएं ताकि हवा बाहर की ओर जाए। अच्छे वेंटिलेशन से घर में ताजी हवा आती है, हवा फ़िल्टर होती है, और हवा का प्रवाह बेहतर होता है। इससे वायरस के कण कम होते हैं और बीमारियां फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही, हवादार घर में धूल के कणों को कंट्रोल रखा जा सकता है।

सावन के मौके पर घर के आंगन से लेकर मंदिर तक में बनाएं जा सकते हैं भगवान शिव से जुड़ी रंगोली के ये डिजाइंस

घर को सजाना हम सभी पसंद करते हैं। वहीं तीज-त्योहार के मौके पर हम घर में साफ-सफाई से लेकर पूजा पाठ तक करते हुए कई चीजों का खासतौर से ध्यान रखते हैं।

सावन का महीना शुरू हो चुका है। हर सोमवार को पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन पाठ-पूजा भी की जाती है। इस मौके पर आप घर के मंदिर में भगवान शिव से जुड़ी कई तरह की रंगोली बनाई जा सकती हैं। सावन के खास मौके पर मंदिर में बनाने के लिए रंगोली के कुछ आसान और खास डिजाइंस।

ओम रंगोली डिजाइन

भगवान शिव का चित्र बनाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आप घर के मंदिरके बाहर बड़े साइज की थाली या पूजा घर में ओम नामः शिवाय लिख सकती हैं या केवल ओम भी रंगों या फूलों से लिख सकती हैं। रंगोली को भरा-भरा बनाने के लिए आप पहले बैकग्राउंड के लिए गोलाई में फ्रेम को तैयार करें।

शिवलिंग रंगोली डिजाइन

घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा के सामने आप रंगों की मदद से शिवलिंग रंगोली के माध्यम से बना सकती हैं। इसके लिए आप काले रंग के अलावा अन्य कई रंग इस्तेमाल कर सकती हैं। शिवलिंग के साथ में आप बेलपत्र और फूल डिजाइन की रंगोली भी बना सकती हैं। बेलपत्र और फूलों के डिजाइन को 3डी बनाने के लिए माचिस की तीली की मदद लें।

त्रिशूल रंगोली डिजाइन

ओम के अलावा आप त्रिशूल के डिजाइन को डमरू के साथ में बना सकती हैं। इसके लिए आप भूरे रंग के साथ नारंगी रंग को चुनकर डिजाइन को पूरा करें। आस-पास चाहे तो बॉर्डर के लिए बेलपत्र रंगोली डिजाइन को बना सकती हैं। त्रिशूल और डमरू के आकार को डेप्थ देने के लिए आप सफेद रंग से आउटलाइन कर सकती हैं।

भगवान शिव रंगोली डिजाइन

अगर आप कला से जुड़ी व्यक्ति हैं और तरह-तरह के चित्र बनाना पसंद करती हैं तो इस तरह से नीले रंग की मदद लेकर भगवान शिव के चेहरे को रंगोली में बना सकती हैं। रंगोली के डिजाइन को पूरा करने के लिए इस तरह के चावल की मदद से बनाया चांद डिजाइन को आकर्षक भी बनाने में मदद करेगा। दीपक जलाकर आप पूजा सकती हैं।

शिवलिंग रंगोली डिजाइन

घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा के सामने आप रंगों की मदद से शिवलिंग रंगोली के माध्यम से बना सकती हैं। इसके लिए आप काले रंग के अलावा अन्य कई रंग इस्तेमाल कर सकती हैं। शिवलिंग के साथ में आप बेलपत्र और फूल डिजाइन की रंगोली भी बना सकती हैं। बेलपत्र और फूलों के डिजाइन को 3डी बनाने के लिए माचिस की तीली की मदद लें।

त्रिशूल रंगोली डिजाइन

ओम के अलावा आप त्रिशूल के डिजाइन को डमरू के साथ में बना सकती हैं। इसके लिए आप भूरे रंग के साथ नारंगी रंग को चुनकर डिजाइन को पूरा करें। आस-पास चाहे तो बॉर्डर के लिए बेलपत्र रंगोली डिजाइन को बना सकती हैं। त्रिशूल और डमरू के आकार को डेप्थ देने के लिए आप सफेद रंग से आउटलाइन कर सकती हैं।

भगवान शिव रंगोली डिजाइन

अगर आप कला से जुड़ी हैं और तरह-तरह के चित्र बनाना पसंद करती हैं तो इस तरह से नीले रंग की मदद लेकर भगवान शिव के चेहरे को रंगोली में बना सकती हैं। रंगोली के डिजाइन को पूरा करने के लिए इस तरह के चावल की मदद से बनाया चांद डिजाइन को आकर्षक भी बनाने में मदद करेगा। दीपक जलाकर आप पूजा सकती हैं।

मोनोक्रोम आउटफिट में स्टनिंग दिखने के लिए इन टिप्स की लें मदद

मोनोक्रोम आउटफिट स्टाइलिंग पिछले काफी समय से चलन में है। जिन महिलाओं के लिए कलर ब्लॉकिंग या कलर व्हील को ध्यान में रखकर सही कलर चुनने में परेशानी होती है, उनके लिए मोनोक्रोम आउटफिट स्टाइल करना अच्छा ऑप्शन है। चूंकि इसमें आपको डिफरेंअ कलर्स सलेक्ट को लेकर बहुत अधिक परेशान नहीं होना पड़ता है और इसे स्टाइलिंग का सेफ ऑप्शन माना जाता है। लेकिन मोनोक्रोम आउटफिट को स्टाइल करना भी इतना आसान नहीं होता। अगर आप मोनोक्रोम आउटफिट कैरी करना चाहती हैं तो यह जरूरी है कि आप इसे स्टाइल करते समय कुछ बातों का खासतौर पर ध्यान रखें। अगर इसकी स्टाइलिंग के दौरान आपसे गड़बड़ी हो जाती है तो आपका लुक एकदम डल व बोरिंग नजर आता है। मोनोक्रोम आउटफिट की स्टाइलिंग के दौरान आपको कलर्स सलेक्शन से लेकर प्रिंट्स व पैटर्न आदि पर भी उतना ही ध्यान देना होता है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको मोनोक्रोम आउटफिट को स्टाइल करने के कुछ बेहतरीन आईडियाज शेयर कर रहे हैं, जिसे जानने के बाद आपको अपने लुक को एन्हॉन्स करना आसान हो जाएगा-

सही हो कलर

मोनोक्रोम आउटफिट में खुद को स्टाइल करते समय जिस बात का सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, वह है कलर। आप किसी भी कलर शेड को सलेक्ट करते समय अपनी स्किन टोन व ओकेजन का खास ख्याल रखें। मसलन, अगर आप ऑफिस में मोनोक्रोम आउटफिट को स्टाइल कर रही हैं तो ऐसे में आप व्हाइट व ब्लैक कलर को प्राथमिकता दे सकती हैं। वहीं एक पॉप लुक के लिए आप कुछ ब्राइट कलर्स व नियॉन कलर सलेक्ट करें।

लाइट व डार्क शेड

कई बार ऐसा होता है कि हम मोनोक्रोम लुक तो कैरी करना चाहते हैं, लेकिन एक ही कलर में डिफरेंट शेड्सको सलेक्ट करते हैं। इस तरह डिफरेंट शेड्स आपके लुक को खास बनाते हैं। हालांकि, इस दौरान भी आपको शेड्स को सलेक्शन स्मार्टली करना होता है। मसलन, लाइट टिंट आंख को आकर्षित करेगा और उस बॉडी पार्ट को अधिक हाइलाइट करेगा, जबकि एक डार्क शेड ध्यान भटकाएगा। इस तरह आप सही शेड सलेक्शन करें।

एसेसरीज का लें सहारा

मोनोक्रोमेटिक लुक कुछ लड़कियों को काफी बोरिंग लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आप कुछ एसेसरीज के जरिए अपने लुक को स्पाइस अप कर सकती हैं। मसलन, आप हैट से लेकर सनग्लासेस, कुछ चंकी ज्वैलरीज आदि को अपने आउटफिट के साथ पेयर करें। यह आपके लुक की एकरसता को ब्रेककरेंगे और आपके लुक को अधिक स्टाइलिश बनाएंगे।

यूं एड करें टेक्सचर

अगर आप मोनोक्रोम आउटफिट को स्मार्टली कैरी करती हैं तो इससे आप अपने लुक में टेक्सचर को भी बेहद खूबसूरती के साथ शामिल कर सकती हैं और अपने लुक को खास बना सकती हैं। मसलन, आप एक स्लीक टॉप के साथ वुलन स्कर्ट को पेयर कर सकती हैं या फिर बल्कि निट स्वेटर के साथ स्लिम या शाइनी पैंट्स को स्टाइलकिया जा सकता है और इस तरह आप खुद को स्टाइल कर सकती हैं।

फुटवियर सलेक्ट

मोनोक्रोमेटिक लुक में आपके फुटवियर भी काफी अहम् होते हैं। इसमें भी आप कलर्स का सलेक्शन इस आधार पर करें कि आप किस तरह का लुक कैरी करना चाहती हैं। मसलन, व्हाइट, ब्लू एंड ब्लैक कलर मोनोक्रोमेटिक लुक में आप मैचिंग फुटवियर कैरीकरके एक एलीगेंट लुक पा सकती हैं। वहीं, अगर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होना चाहती हैं तो ऐसे में प्रिंटेड या फिर ब्राइट व नियॉन कलर को चुन सकती हैं। यह आपके लुक को एकदम से चेंज कर देगा।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

फिर बिगड़ी आडवाणी की तबीयत, अस्पताल में भर्ती

नईदिल्ली। छुट्टी मिलने के लगभग एक महीने बाद, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को मंगलवार को फिर से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, 96 वर्षीय की हालत स्थिर है और निगरानी में हैं। आडवाणी को न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. विनीत सूरी की देखरेख में भर्ती कराया गया है। पिछले महीने अपोलो अस्पताल में भर्ती होने से कुछ दिन पहले, आडवाणी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी भर्ती कराया गया था। आडवाणी ने 1998 से 2004 तक गृह मंत्री और 2002 से 2004 तक उप प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2009 के आम चुनाव के दौरान भाजपा के प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार थे। इस साल 31 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में अपने आवास पर आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया।

स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन

नईदिल्ली। इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को वापस लेने की मांग को लेकर मंगलवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वर्तमान में, केंद्र सरकार जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाती है। टीएमसी, कांग्रेस, आप और एनसीपी (एससी) जैसे विभिन्न दलों के सांसद (सांसद) संसद के मकर द्वार की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने हाथों में कर आतंकवाद लिखी तख्तियां पकड़ रखी थीं और अपनी मांग पर जोर देने के लिए नारे लगाए। इससे पहले, टीएमसी सांसदों ने इस मुद्दे को संसद में उठाया और पार्टी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी वापस लेने का अनुरोध किया था।

राजद प्रमुख लालू और तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें

पटना। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) राजद प्रमुख लालू यादव और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर शिकंजा कस दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव और आठ अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष दायर किया गया। मामले पर विचार के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की। मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में प्रसाद के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी नियुक्तियों से संबंधित है। पूरक आरोपपत्र विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की। ईडी का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी से उपजा है।

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई, ईडी मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आप नेता की जमानत याचिका का विरोध किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसके पास कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में उनकी गहन संलिप्तता दिखाने के लिए दस्तावेज हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनीं। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था।

भाजपा को घेरने के लिए उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सुप्रीमो और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंगलवार को 3 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, ठाकरे संभवत: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे पर शिव सेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि यह एक राजनीतिक यात्रा है। वह राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आदि सहित इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे। राउत ने आगे बताया कि हम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट-बंटवारे की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। जैसा लोकसभा चुनाव में किया गया था, वैसा ही किया जायेगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने कहा मुंबई में होने वाले कार्यक्रम में राहुल गांधी और खड़गे भी मौजूद रहेंगे।

बांग्लादेश में हिंसा के बीच केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

बांग्लादेश मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों ने दिखाई मोदी सरकार के साथ एकजुटता

नईदिल्ली। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुई उथल पुथल के बीच मोदी सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुला कर सभी दलों को बताया कि सरकार क्या एहतियाती उपाय कर रही है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बैठक में मौजूद राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात और भारत पर उससे पड़ने वाले असर को देखते हुए उठाये जा रहे कदमों की जानकारी दी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नेताओं को बताया कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर आईं शेख हसीना भारत में हैं। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री ने आगे भी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर भरोसे में लेते रहने का और अन्य जानकारियों से अवगत कराने का आश्वासन दिया है। विदेश मंत्री ने सहयोग और समर्थन के लिए राजनीतिक दलों का शुक्रिया भी अदा किया।

बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, टीएमसी, जनता दल युनाइटेड, एनसीपी, आरजेडी समेत विभिन्न दलों के नेताओं की मौजूदगी थी। सरकार की ओर से विदेश मंत्री के अलावा बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद थे। बैठक के बाद राहुल गांधी समेत विभिन्न नेताओं ने कहा कि वह बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत सरकार के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को सही रणनीति बनाने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि बैठक में राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से सवाल भी पूछा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ कहीं उसके पीछे कोई विदेशी हाथ तो नहीं है। सोमवार शाम को भी राहुल गांधी ने लोकसभा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के पास जाकर उनसे बांग्लादेश के मुद्दे पर बातचीत की थी।

हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को इस मुद्दे पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। उस

बैठक में सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। मोदी के साथ बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थे। शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें पड़ोसी देश के हालात के बारे में जानकारी दी।

इस बीच, भारत ने बांग्लादेश से लगती सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम के मद्देनजर 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी यूनिट के लिए 'हाई अलर्ट' जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ के कार्यवाहक महानिदेशक (डीजी) दलजीत सिंह चौधरी और अन्य वरिष्ठ कमांडर ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल के अग्रिम मोर्चे का दौरा भी किया। बताया जा रहा है कि बीएसएफ ने अपने सभी 'फील्ड कमांडर' को निर्देश दिया है कि वह सभी कर्मियों को सीमा पर ड्यूटी पर तुरंत तैनात करें। बताया जा रहा है कि बीएसएफ प्रमुख के अगले कुछ दिनों तक इस क्षेत्र में रहने की उम्मीद है।

इस बीच, दिल्ली स्थित बीएसएफ के प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश सीमा पर स्थिति अभी सामान्य है। उन्होंने कहा, ''जवान हालिया घटनाक्रम से अवगत और सतर्क हैं तथा किसी भी अप्रत्याशित हालात से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।''

प्रधानमंत्री और देश के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है कांग्रेस: निशिकांत दुबे

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए उस पर अपने कार्यकाल के दौरान डीबीटी यानी डालमिया, बिड़ला और टाटा जैसे कुछ व्यापारिक समूहों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। उन्होंने बजाज को भी इस सूची में शामिल किया और इसे डीबीबीटी योजना का नाम दिया। दुबे की टिप्पणी विपक्ष के आरोपों के जवाब में की गई थी कि वर्तमान सरकार अरबपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनियों का समर्थन करती है।

दुबे ने लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कांग्रेस के समय धनशोधन विरोधी कानून तथा आयकर से जुड़े कानूनों को सख्त किया गया था, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में ईमानदारी से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा, वो जेल जाएगा। दुबे ने कहा कि आज जब अन्य देशों का आकलन करेंगे तो पता चलेगा कि आज भी भारत दुनिया के लिए आशा की किरण है क्योंकि यहां विकास दर सात प्रतिशत है।

दुबे ने कुछ राजनेताओं के व्यवहार में स्पष्ट विरोधाभास की ओर भी इशारा किया। उन्होंने उल्लेख किया कि अडानी और अंबानी की आलोचना करने वाले कई लोग अनंत अंबानी की शादी में मौजूद थे, लेकिन अब संसद में उनके विरोध में मुखर हैं, जहां उद्योगपति अपना बचाव नहीं कर सकते। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बजट को लेकर अराजकता फैला रहे हैं तथा उस पद का क्या हाल कर रहे हैं जिस पर बाबू जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, वाईवी चव्हाण और शरद पवार जैसे लोग आसीन रह चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है और उसने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। दुबे ने कहा, ''आज देश के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से हैं, अगर वह ओबीसी की सुरक्षा की बात करते हैं तो आप (कांग्रेस) ओबीसी-ओबीसी करने लगते हैं।''

तिहाड़ जेल के बाहर भाजपा का विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की

नईदिल्ली। कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने मंगलवार को तिहाड़ जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा की ओर से प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर तख्तियां लेकर नारे लगाए, जहां केजरीवाल बंद हैं।

यह दावा करते हुए कि शासन और प्रशासन पंगु हो गया है, भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आदेश के बाद जेल से सरकार चलाने पर जोर देने के बजाय केजरीवाल को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सरकार का कोई भी मंत्री किसी भी मामले की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और वे अधिकारियों पर दोष मढ़ने में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और दिल्ली के लोग इस गन्दी स्थिति में पिस रहे हैं।

उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं है, जिसने दिखाया है कि आप सुप्रीमो कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं। अदालत ने कहा कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी और प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद उनके खिलाफ साक्ष्यों का चक्र बंद हो गया और यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के या अवैध था। अदालत ने कहा कि केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं हैं, बल्कि मैगसायसाय पुरस्कार विजेता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं।

बांग्लादेश पर राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री, स्थिति पर हमारी नजर

■ शेख हसीना ने भारत आने की मांगी थी इजाजत

नईदिल्ली। विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत बांग्लादेश में अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है, जो अपनी प्रधान मंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद राजनीतिक संकट की चपेट में है। राज्यसभा में अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि हमारी समझ यह है कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नेताओं के साथ बैठक के बाद, प्रधान मंत्री शेख हसीना ने स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। बहुत ही कम समय में, उन्होंने कुछ समय के लिए भारत आने की मंजूरी का अनुरोध किया। वह सोमवार शाम दिल्ली पहुंचीं।

जयशंकर ने बताया कि हम अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में हैं। अनुमानत: वहां 19,000 भारतीय नागरिक हैं जिनमें से लगभग 9000 छात्र हैं। जुलाई में बड़ी संख्या में छात्र लौट आए। उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यकों की स्थिति के संबंध में भी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समूहों और संगठनों द्वारा पहल की खबरें हैं।

मंत्री ने बताया कि स्वाभाविक रूप से, कानून-व्यवस्था बहाल होने तक हम बेहद चिंतित रहेंगे। इस जटिल स्थिति के वीडियो में हमारे सीमा सुरक्षा बलों को विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। पिछले 24 घंटों में, हम ढाका में अधिकारियों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी ढाका में जुटे। हमारी समझ यह है कि सुरक्षा प्रतिष्ठान के नेताओं के साथ बैठक के बाद, प्रधान मंत्री शेख हसीना ने स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का निर्णय लिया।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज

कोलंबो। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा

और अंतिम वनडे मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। पहले दो मैच में बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन से आहत भारतीय क्रिकेट टीम के पास सीरीज बचाने का यह आखिरी मौका है। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मैच भारतीय समयानुसार 2:30 बजे शुरू होगा।

भारत को अगर श्रीलंका से 27 साल बाद सीरीज गंवाने से बचना है तो उसको बुधवार को होने वाले तीसरे वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में स्पिनरों पर हावी होकर खेलना होगा। भारत को श्रीलंका के खिलाफ आखरी बार वनडे सीरीज में हार का सामना 1997 में करना पड़ा था। अर्जुन रणतुंगा की अगुवाई वाली टीम ने तब सचिन तेंदुलकर की भारतीय टीम को तीनों मैच में हराया था। भारत और श्रीलंका के बीच तब से 11 वनडे सीरीज हो चुकी है और इन सभी में भारतीय टीम विजयी रही। हालांकि, टीम इंडिया तीसरा वनडे जीतने के बावजूद सीरीज नहीं जीत पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि क्योंकि पहला मैच टाई छूटने के बाद दूसरे मैच में उसे 32 रन से हार का सामना करना पड़ा था।

प्रेमदासा की पिच पर स्पिनरों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। हालांकि, पारी की शुरुआत में तेज़ गेंदबाज़ों प्रभावी हो सकते हैं। पिछले 5 सालों में इस मैदान पर 82त्न टीमों ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत और श्रीलंका के बीच पहले वनडे में 18 विकेटों में से 13 विकेट स्पिनरों ने लिए जो दर्शाता है कि इस पिच पर स्पिन गेंदबाजी का बोलबाला है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 166 अंक लुढ़का निफ्टी 24,000 के नीचे

नईदिल्ली। शेयर बाजार में 6 अगस्त को फिर से भारी हलचल देखने को मिली। शेयर बाजार शुरुआती बढ़त गंवाकर स्टॉक बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 166 अंकों की गिरावट के साथ 78,593.07 पर बंद हुआ और निफ्टी 24,000 के नीचे 23,992.55 पर समाप्त हुआ। लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 166.33 अंक या 0.21 प्रतिशत गिरकर 78,593.07 पर बंद हुआ, जिसमें 17 शेयरों में गिरावट और 13 में बढ़त रही। इंडेक्स ने दिन की शुरुआत तेज बढ़त के साथ की और 1,092.68 अंक या 1.38 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 79,852.08 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, लेकिन बाद में 78,496.57 के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह, एनएसई निफ्टी 63.05 अंक या 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,992.55 पर बंद हुआ। इंट्रा-डे ट्रेड में यह 327 अंक या 1.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,382.60 तक पहुंचा।

सिम्फनी के शेयरों में 20 प्रतिशत की तेजी

नईदिल्ली। सिम्फनी कंपनी का शेयर आज बाजार में धूम मचा रहा है। इसकी कीमत 20त्न बढ़कर 1474.90 रुपये पर पहुंच गई है, इसके साथ कंपनी ने अपर सर्किट हिट कर दिया। पिछले साल जून में भी इसकी कीमत 1289.40 रुपये तक पहुंची थी, लेकिन आज उससे भी आगे निकल गई। साल 2018 में जनवरी में ये शेयर 2212.75 रुपये तक पहुंचा था। इस शेयर में इतनी तेजी इसलिए आई है क्योंकि कंपनी ने पिछली तिमाही (अप्रैल से जून 2024) में अच्छी कमाई रिपोर्ट की है। साथ ही, कंपनी ने अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देने और कुछ शेयर वापस खरीदने का भी फैसला किया है, जिससे निवेशकों का उत्साह और बढ़ गया है। कंपनी ने पिछले साल की तुलना में इस साल अप्रैल से जून के बीच अपनी कमाई में चार गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की है। इस बार ये बढ़कर 88 करोड़ रुपये हो गया।

वेदांता ने जारी किया जून तिमाही का रिजल्ट

नईदिल्ली। खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड ने मंगलवार को जून तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया। वेदांता ने बताया कि 2024-25 की पहली तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटिड नेट प्रॉफिट 36.5 प्रतिशत बढ़कर 3606 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वेदांता ने वित्त वर्ष 2023-24 की इसी तिमाही में 2,640 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, अप्रैल-जून अवधि में वेदांता की कंसोलिडेट इनकम एक साल पहले की अवधि में 34,279 करोड़ रुपये से बढ़कर 36,698 करोड़ रुपये हो गई। वेदांता लिमिटेड, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। यह भारत, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, लाइबेरिया, संयुक्त अरब अमीरात, कोरिया, ताइवान और जापान में फैली दुनिया की अग्रणी प्राकृतिक संसाधन कंपनियों में से एक है और तेल और गैस, जस्ता, सीसा, चांदी में कारोबार करती है।

जुलाई में 11 प्रतिशत महंगी हुई वेज थाली

नईदिल्ली। इस साल जुलाई में खाना खाना महंगा हो गया है। जुलाई में वेज (शाकाहारी) और नॉन वेज (मांसाहारी) दोनों थाली की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि सालाना आधार पर दोनों थाली की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। वेज थाली में रोटी, चावल, दाल, दही, सलाद के साथ ही प्याज, आलू, टमाटर होते हैं। मांसाहारी थाली में शाकाहारी थाली के काफी खाद्य पदार्थ होते हैं। लेकिन दाल की जगह चिकन (ब्रॉयलर) होता है। घर में पकाई जाने वाली इन थालियों की औसत मूल्य की गणना उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में इस थाली में शामिल भोजन को बनाने में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों के आधार पर की जाती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की 'रोटी राइस रेट' नाम से जारी रिपोर्ट के अनुसार इस साल जून में शाकाहारी थाली की कीमत 29.4 रुपये थी, जो जुलाई में बढ़कर 32.6 रुपये हो गई।

छोटी उम्र से ही करें वित्तीय प्रबंधन, बजट बनाकर कम कर सकते हैं खर्च

विशांत श्रीवास्तव

मेरे एक मित्र अपनी 18 वर्ष की बेटी के बारे में चिंतित थे। वह हॉस्टल में रहकर अपने खर्चों का मैनेजमेंट कर रही है। यह दिलचस्प है कि मेरे मित्र और उनकी पत्नी दोनों ही अपने कॉलेज के दिनों में हॉस्टलर थे और वे हॉस्टल में मिलने के बाद एक दूसरे के करीब आए और शादी की। इसलिए, जब उन्होंने कहा कि उन्हें चिंता है कि उनकी बेटी कैसे अपने खर्चों का मैनेजमेंट करेगी, तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अपने पैसे का मैनेजमेंट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब आपने बचपन में कभी इस पर ध्यान नहीं दिया हो।

जब मैं पैसे का प्रबंधन करने की बात करता हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ एप्स पर पैसे खर्च करना नहीं है। इसका मतलब है कि एक सीमित बजट में रहना और पैसे खत्म होने का फिक्र करते रहना। छोटे बच्चों और युवाओं को जल्द से जल्द वित्तीय साक्षरता हासिल करनी चाहिए। यह मुश्किल नहीं है, खासकर आजकल ऑनलाइन उपलब्ध संसाधनों की मदद से। वित्तीय साक्षरता का मतलब है कि आप अपने पैसे से समझदारी से फैसले लेना सीखें। पैसे का बुनियादी वित्तीय ज्ञान आपकी भविष्य की वित्तीय आदतों और लक्ष्यों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है।

अगर आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं और पैसे खर्च करना चाहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। यह भी जरूरी है कि आप दोस्तों की खरीदारी से प्रभावित न हों। इसके लिए अपने माता-पिता से पूछें कि कितना खर्च कर सकते हैं। अगर वे कोई सीमा नहीं बताते तो अपनी सीमाएं स्वयं तय करें। 1,000 रुपये को एक

ऐसे बजट के रूप में सोचें जो दोस्तों के साथ लंच या मूवी पर खर्च करने के लिए सही हो। आपका लक्ष्य इसमें से बचत करना होना चाहिए और पूरी राशि खर्च नहीं करनी चाहिए। अगर इससे अधिक खर्च करते हैं और किसी दोस्त से उधार लेते हैं, तो यह एक खराब वित्तीय आदत है।

कई युवा पैसे उधार लेने की आदत में फंस जाते हैं। पैसे उधार लेना अच्छी बात नहीं है क्योंकि यह दिखाता है कि आप अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर रहे हैं। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आप बजट के भीतर रहें और खर्च की सीमा निर्धारित करें। यह देखें कि आपको वास्तव में क्या चाहिए और उसकी लागत क्या है। अपने खर्चों पर नजर रखने के लिए एक हफ्ते के लिए एक छोटी डायरी रखना एक अच्छा कदम है, ताकि आप समझ सकें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। जब आप अपने खर्चों का विश्लेषण करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप कई गैर-जरूरी चीजों पर पैसे खर्च कर रहे हैं। बचत और निवेश के बारे में सोचना शुरू करें। आप सोच सकते हैं कि अभी बचत और निवेश की क्या जरूरत है, लेकिन यही समय है जब आपको यह समझना चाहिए। इससे आपके रिटर्न कई सालों में बढ़ेंगे और आपकी बचत तेजी से बढ़ेगी।

बजट बनाने के बारे में सोचें कि किस पर खर्च करना है। कितना बचाना है और कितना निवेश करना है। बजट आपके फाइनेंस को मजबूत करने के सबसे उपयोगी साधनों में से एक है। यह जानना कि आपका पैसा पूरे महीने कहां खर्च हो रहा है, वित्तीय साक्षरता के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। उदाहरण के लिए, अपने खर्चों की समीक्षा करने से आप बेकार की स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन, हर हफ्ते होटल जाने और अवांछित सदस्यता शुल्क का पता लगा सकते हैं। इन खर्चों को कम करने से आप पैसे बचा सकते हैं। कई बजटिंग ऐप और साधन हैं जो आपकी इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। आप अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से शुरुआत कर सकते हैं, जो संभवत: एक मुफ्त बजटिंग टूल प्रदान करता है। आप ऑनलाइन बजट कैलकुलेटर का भी उपयोग कर सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय योजना आपके जीवन में कैसे मदद कर सकती है। आप अपने करियर की शुरुआत में ही वित्तीय आदतें विकसित करेंगे, जो आपकी जीवनशैली को सुधारेंगी।

बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षकों और पालकों के बीच संवाद आवश्यक : साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज जशपुर जिले के ग्राम बंदरचुंआ में आयोजित मेगा शिक्षक पालक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों की अच्छी शिक्षा और इनके उन्नत भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि अभिभावक शिक्षकों से नियमित रूप से संवाद करें जितना अधिक शिक्षक और अभिभावक संवाद प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, उतना ही अधिक बच्चों का रचनात्मक विकास होगा उन्होंने पालकों तथा शिक्षकों से कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें बेझिझक बोलने के लिए तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विकास का मूलमंत्र हैं। यह केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है बल्कि किसी भी क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने के लिए भी शिक्षा बेहद जरूरी है। एक शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति दोनों ही जीवन जीते हैं लेकिन दोनों के जीवन की गुणवत्ता में काफी अंतर देखने में आता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक बच्चे के भीतर आई जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश करें। घर पहुंचने पर यह जरूर पूछें कि बच्चे ने आज क्या सीखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदरचुंआ के स्कूल से पुराना लगाव है। यहां के शिक्षक और जागरूक पालकों के कारण इस स्कूल में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के समाज में पुरातन काल से ही शिक्षा का काफी महत्व रहा है। भारत विश्वगुरू कहलाता था। पूरी दुनिया से लोग यहां के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति लाई गई है जिसे प्रदेश में लागू किया गया है। इसमें नैतिक शिक्षा को भी शामिल किया गया है। संस्कार सिखाने के साथ ही रोजगार के लिए भी विद्यार्थियों को तैयार किया जा रहा है। छात्रों के स्किल बिल्डिंग पर काम किया जा रहा है, ताकि उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गर्मी में समर कैंप लगाए गए। बच्चों को बहुत सी रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय स्कूलों में पालक शिक्षक बैठक का नियमित आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी पालकों से अनुरोध किया कि स्कूल आएं और अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई और प्रोग्रेस के बारे में जाने। उन्होंने कहा कि स्थानीय बोली भाषा में भी पढ़ाई को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके लिए किताबें भी उपलब्ध कराई जायेगी। पीएम श्री योजना से स्कूलों में संसाधनों को बेहतर किया जायेगा। टॉपर बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। सरस्वती सायकल योजना से छात्राओं को सायकल वितरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नालंदा परिसर की तर्ज में प्रदेश के 22 जिलों में पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा है, इसमें जशपुर और कुनकुरी में भी नालंदा परिसर खोलने जा रहे हैं। यहां बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के किताबें वातावरण भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री को पालक शिक्षक बैठक में 12 मुख्य गतिविधियों के बारे में स्कूल के बच्चों ने ही बताया। पालकों ने भी अपने अनुभव बताए। पालक श्री हरिसेवक चौहान ने बताया कि उनका एक पोता यहां से पढ़कर अभी एमएससी कर रहा है और एक यहां से ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रहा है। वे एक जागरूक पालक हैं जो अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री की धर्म पत्नी श्रीमती कौशल्या साय ने भी संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि बंदरचुंआ स्कूल में सन 1997-98 से स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के आयोजन में शामिल होने का मौका मिल रहा है। यहां के बच्चों के साथ दिल से जुड़ाव है। परीक्षा से पहले भी यहां बच्चों के मार्गदर्शन के लिए पहुंचते रहे हैं। बच्चों और पालकों से यही बात कहना चाहती हूं कि परीक्षा परिणाम के लिए तनाव नहीं लेना है। पूरी मेहनत से परीक्षा देना है। नंबर कम ज्यादा हो तो तनाव बिल्कुल न लेना है। परिवार पहली पाठशाला है और माता पिता पहले गुरु हैं।

मुख्यमंत्री की घोषणाएं - इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बंदरचुंआ में सर्वसुविधायुक्त बस स्टैंड निर्माण की घोषणा की। साथ ही उन्होंने प्राथमिक शाला बंदरचुंआ से छेराघोघरा चौक तक सड़क किनारे सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने, भुइयार बस्ती से सरना पहुंच मार्ग में सड़क और पुल, गायत्री मंदिर और शिव मंदिर के जीर्णोद्धार, आश्रम छात्रावास को 50 सीटर से 100 सीटर करने तथा बंदरचुंआ में मिनी स्टेडियम निर्माण की घोषणा की।

40 गांवों के फ्लोराइड रिमूवल प्लांट बंद : हाईकोर्ट ने मामले में लिया संज्ञान

बिलासपुर। गरियाबंद जिले के गांवों में बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार हो रहे हैं। ये बीमारी पानी में फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा से होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए जिले के 40 गांवों में 6 करोड़ की लागत से फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए गए। लेकिन वह कुछ महीने में ही बंद हो गए। हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया है। मामले में नोटिस के बाद शासन ने जवाब दिया कि इसकी जानकारी लेकर उचित कार्रवाई होगी और जवाब पेश किया जाएगा। कोर्ट ने प्रकरण में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग को दो सप्ताह में व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 14 अगस्त को होगी। दरअसल, गरियाबंद जिले के इन प्रभावित गांवों में हर साल 100 से ज्यादा स्कूली छात्रों को डेंटल फ्लोरोसिस होता है। इन गांवों में 50 से 60 बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस से ग्रसित मिल रहे हैं वहीं देवभोग ब्लॉक के गांवों में कुल पीड़ितों की संख्या 2 हजार से भी ज्यादा है। साल 2016 में शासन-प्रशासन को जांच में फ्लोराइड ज्यादा होने की जानकारी लगी। देवभोग ब्लॉक के 40 गांव के स्कूलों में जो पेयजल सप्लाई हो रही है वहां 8 गुना तक ज्यादा फ्लोराइड था। प्रशासन ने कार्य योजना बना कर सभी प्रभावित स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाने का फैसला लिया है। हाईवे के किनारे गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं हाईवे कंपनी की जवाबदारी है कि गड्ढे को भरे-वरुण पांडे भाजपा नेता वरुण पांडे ने कहा है कि नेशनल हाईवे आरके नगर चौक विधि डायग्नोस्टिक बर्फानी धाम के पास हाईवे के किनारे गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं .

भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान 11 से

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में 12 लाख तिरंगा झंडे बांटने की घोषणा की है।

इस अभियान को लेकर भाजपा की एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि भाजपा एक संगठनात्मक और वैचारिक आंदोलन है, जो गैर-राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

कोविड-19 महामारी के समय भी भाजपा ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत जन सेवा की थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 11 से 15 अगस्त तक एक पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा. जिसके दौरान हर घर में तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जाएगा। 11, 12 और 13 अगस्त को सर्व व्यापी तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा, जो युवा मोर्चा के नेतृत्व में हर विधानसभा में आयोजित होगी। इस दौरान महापुरुषों के माल्यार्पण के साथ स्वच्छता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मौन जुलूस भी निकाला जाएगा। प्रदेश सचिवालय में हर कार्यकर्ता सभी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने बताया कि इस देशव्यापी कार्यक्रम को लेकर की गई बैठक में संकल्प लिया गया है कि छत्तीसगढ़ इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभाएगा। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी, टांकराम वर्मा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विधायक राकेश अग्रवाल और अवधेश चंदेल भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री के समक्ष डिजिटल एप्प ई-जादुई पिटारा की खूबियों का किया गया प्रदर्शन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के समक्ष जशपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंदरचुआं में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संचालित डिजिटल एप ई- जादुई पिटारा की खूबियों का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षिका श्रीमती शशिकिरण कश्यप ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक छोटी सी कहानी बताई। कक्षा 5वीं के बच्चे प्रतीक कुजूर, स्नेहा मिंज और प्रियंका बाई ने किस तरह खेल-खेल में इस एप के माध्यम से सिखाया जाता है उसका बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया। ई-जादुई पिटारा नई शिक्षा नीति ने तहत ही बनाया गया है ताकि बच्चों को पढ़ाई बोझ न लगे और नवाचार के माध्यम से बच्चे कठिन विषयों को भी खेल खेल के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। यह एप में मुख्य रूप से प्राइमरी तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। इस एप के माध्यम से बच्चों को उनके रुचि के अनुकूल बहुत ही सरल और मनोरंजक तरीके से सिखाया जाता है। इस एप्प में कहानियां, बालगीत, पहेलियां, कार्ड, ऑडियो पुस्तकें, खिलौने और खेल, हैंडबुक चार्ट और जादुई पिटारा बॉक्स के माध्यम से बच्चों के लिए रचनात्मक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इस एप से बच्चे, शिक्षक और पालक जुड़े रहते हैं। कोई भी स्कूल में यदि कोई भी रचनात्मक गतिविधि होती है तो उसे इस एप में अपलोड कर सकते है।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

पिछले वर्ष खरीदा गया धान बारिश में सड़ रहा: बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार की लापरवाही के चलते लाखो टन धान का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है और धान बारिश में भीगकर सड़ रहा है। सरकार पिछले वर्ष खरीदे गये धान का न पूरा उठाव कर पाई और न ही धान को सुरक्षित रखने का पूरा इंतजाम किया है। इस वर्ष भी खरीफ की फसल लग गई है लेकिन पिछले वर्ष का धान सड़ने छोड़ दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के लापरवाही के चलते प्रदेश में 22 लाख क्विंटल से अधिक धान जिसकी कीमत 682 करोड़ रुपए से अधिक है वह खराब हो गई है। डबल इंजन की सरकार धान को सडा कर अन्नदाताओं की मेहनत का अपमान कर रही। धान का सड़ना धान घोटाला की ओर इशारा कर रहे हैं। जानबूझकर धान के रखरखाव पर लापरवाही बरता गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान बीते 5 वर्षों में बंपर धान की खरीदी हुई थी और समय पर कस्टम मिलिंग हो गया था। धान के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त व्यवस्था धान खरीदी से पहले कर दी जाती थी भाजपा की सरकार बनने के बाद धान खरीदी केंद्रो में भारी लापरवाही सामने आया है।

तीन गौ अभ्यारण में सवा करोड़ पशुधन कैसे रहेंगे?

रायपुर। राज्य सरकार के द्वारा 15 अगस्त को तीन गौ अभ्यारण बनाने की शुरुआत करने पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूछा की भाजपा सरकार प्रदेश की जनता को बताये तीन गौ अभ्यारण में प्रदेश की सवा करोड़ पशुधन कैसे रहेंगे? इनमे 64 प्रतिशत गौवंश है कांग्रेस की सरकार ने पशुधन की संख्या को देखते हुए प्रदेश में 10000 से अधिक गौठानों का निर्माण किया था। जिसके चलते पूरे प्रदेश में साढ़े तीन लाख सरकारी जमीन सुरक्षित हुआ था। जिसमें से 6000 से अधिक गौठान आत्मनिर्भर बन गए थे। जिन्हे महिला स्वास्थ्य समूह संचालित करती थी। जहां सरकार एक रुपए भी खर्च नहीं करती थी। इस योजना की तारीफ नीति आयोग ने भी किया था और अन्य प्रदेशो को लागु करने की सिफारिश भी किया था। भाजपा की सरकार बनते ही इन गौठानों में ताला लगा दिया गया है। जिसके चलते पशुधन भटक रहे हैं। किसान फसलों की चराई से परेशान है और सड़कों में भी पशुधन के चलते दुर्घटनाएं हो रही। भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में 8 महीने में ही लगभग 800 से अधिक पशुधन की दुर्घटना से मौत हो गई है। प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार राजनीतिक दुर्भावना के कारण गौठानों में ताला लगा दिया है।

जल जीवन मिशन का 1200 करोड़ क्यों नही दे रही है? केन्द्र सरकार

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार पर छत्तीसगढ़ की उपेक्षा और भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्ष में रहते हुये भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस की सरकार पर झूठा आरोप लगाते थे कि केन्द्रीय योजनाओं का काम छत्तीसगढ़ में नही हो रहा है। अब प्रमाणित हो चुका है कि कांग्रेस की सरकार ने केन्द्रीय योजनाओं के क्रिन्यावयन में भी बेहतरीन काम किये थे जल जीवन मिशन मे पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार हुये काम का 1200 करोड़ केन्द्र की मोदी सरकार ने दुर्भावनापूर्वक रोक रखा है। इसी तरह पीएम आवास, बागवानी मिशन, ग्रामीण सड़क योजना भी डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दुर्भावना और पूर्वाग्रह की भेंट चढ़ गयी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि 2022 तक हर घर में नल लगाने का दावा करने वाले भाजपा नेता जल जीवन मिशन के छत्तीसगढ़ के हक के 1200 करोड से अधिक का भुगतान केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा रोके जाने पर मौन क्यों है? अपने चहेते भाजपाई ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने बार-बार स्पेसिफिकेशन बदला जा रहा है। ठेकेदारों को चिन्हित करके उनके भुगतान रोके जा रहे हैं.

6 फर्जी फर्मों के नेटवर्क का पर्दाफाश

रायपुर. सीजीएसटी मुख्यालय, रायपुर के अधिकारियों ने तलाशी अभियान चलाकर 6 फर्जी फर्मों के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. ये फर्म वस्तुओं और सेवाओं की किसी भी प्रकार की आपूर्ति किए बिना केवल फर्जी चालान बनाने में सक्रिय रूप से लगे हुए थे. विशेष खुफिया जानकारी और डाटा विश्लेषण के आधार पर पता चला था कि जीएसटी के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लेने एवं आगे पारित करने के लिए कई फर्जी फर्में बनाई गई है. व्यापक निगरानी के बाद उस स्थान की पहचान कर सीजीएसटी की टीम ने कार्रवाई की. सीजीएसटी रायपुर आयुक्त मो. अबु सामा आईआरएस ने बताया, जांच से पता चला है कि रायपुर निवासी बादल गौर इन फर्जी फर्मों को बनाने और चलाने के मामले में मास्टरमाइंड है. तथ्यों और सबूतों के साथ पूछताछ करने पर मास्टरमाइंड बादल गौर ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित करने के उद्देश्य से काल्पनिक फर्मों का एक समूह बनाने की बात स्वीकार की.

छत्तीसगढ़ में अब तक 676.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 676.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 06 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1509.7 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 321.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 553.2 मिमी, बलरामपुर में 845.6 मिमी, जशपुर में 536.1 मिमी, कोरिया में 575.3 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 582.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। इसी प्रकार, रायपुर जिले में 599.0 मिमी, बलौदाबाजार में 742.0 मिमी, गरियाबंद में 647.0 मिमी, महासमुंद में 499.6 मिमी, धमतरी में 668.6 मिमी, बिलासपुर में 624.7 मिमी, मुंगेली में 670.7 मिमी, रायगढ़ में 571.1 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 343.3 मिमी, जांजगीर-चांपा में 601.6 मिमी, सक्ती 521.5 कोरबा में 792.3 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 614.3 मिमी, दुर्ग में 443.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 553.1 मिमी औसत वर्षा अब तक रिकार्ड की गई।

माता-पिता बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को पहचानें : कलेक्टर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर शासकीय स्कूलों में मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट प्रारंभ किए गए है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह मौदहापारा स्थित शहीद स्मारक उच्चर माध्यमिक स्कूल के पैरेंट्स-टीचर मीट में शामिल हुए। कलेक्टर डॉ. सिंह ने पालकों से संवाद किया और उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए अपने अनुभव भी साझा किए। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि निजी स्कूलों की तर्ज पर जिले के शासकीय स्कूलों में मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट की शुरूआत की गई है। मुख्यमंत्री साय की

पहल पर पढ़ाई के स्तर को बेहतर करने के लिए नई शुरूआत है। इस मीटिंग के जरिए स्कूल के विकास में पालकों के सुझाव पर चर्चा होगी और इससे बच्चों की समस्या भी दूर करने में यह बैठक महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री साय ने भी आज पालकों से शासकीय स्कूलों में बातचीत की। ऐसे कार्य संवेदनशील मुख्यमंत्री ही कर सकते है। इस मीटिंग के माध्यम से पालकों के अनुभव साझा होते है और स्कूल की गुणवत्ता, सुगमता और बच्चों के भविष्य को संवारने में मदद मिलती है। डॉ. सिंह ने कहा कि बच्चे अपनी प्रतिभा को लेकर पैदा होते है और उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को पहचानना भी आवश्यक है। बच्चों के साथ मित्रता होनी भी जरूरी है, ताकि वह हर बातों को साझा कर सकें। डॉ. सिंह ने कहा कि बच्चों की इच्छा जानने जरूरी है, इसके बाद ही बेहतर भविष्य का निर्माण किया जाए। शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की प्रतिभाओं में भी कोई कमी नहीं है। शासकीय स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। इस कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने पैरेंट्स बच्चों को लेकर सवाल किए। इस पर कलेक्टर ने गंभीरता से जवाब दिए। साथ ही पैरेंट्स ने स्कूल व पढ़ाई की प्रसंशा की। इस अवसर पर कलेक्टर ने अपने पुराने अनुभव भी पैरेंट्स मीटिंग में साझा किए। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल, स्कूल प्राचार्य, शिक्षक, बड़ी समय में पालकगण, छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

नेताम ने केन्द्रीय मंत्री जुएल ओराम से की मुलाकात

रायपुर। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास मंत्री रामविचार नेताम ने मंगलवार को अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम से सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री ओराम से छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति-जनजाति सहित कमजोर व पिछड़े वर्गों के विकास के संबंध में विस्तार से चर्चा की। आदिम जाति मंत्री नेताम ने इस दौरान केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम से प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2022-23 शेष राशि 74 करोड़ 69 लाख 27 हजार रूपए जारी करने का अनुरोध किया। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1653 करोड़ 71 लाख 20 हजार रूपए का प्रावधान किया गया था। मंत्री नेताम ने इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री ओराम से आदिवासी उप योजना के विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के तहत 162 करोड़ रूपए और छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा के लिए 55 करोड़ 14 लाख 35 हजार रूपए के प्रस्तावों को वर्ष 2024-25 में शामिल कर स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.